सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 72, नई दिल्ली । शुक्रवार, 24 मई 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जब तक आप चीजों को अलग तरीके से नहीं देखते तब तक आप उसे अलग तरीके से नहीं कर सकते।

03 दिल्ली हरियाणा समेत 8 राज्यों की 58 सीटों पर 25 मई को

06 महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से लें प्रेरणा

08 सैलरी ना मिलने पर निगम शिक्षक काली पट्टी बांधकर करेंगे चुनाव ड्यूटी

सड़क सुरक्षा ओमनी फाउंडेशन और परिवहन विशेष ने सड़क सुरक्षा बैठक में व्यावहारिक प्रवर्तन पर जोर दिया

सड़क सुरक्षा जागरूकता और प्रवर्तन को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, सड़क सुरक्षा ओमनी फाउंडेशन की कोर टीम ने परिवहन विशेष के सहयोग से हाल ही में एक व्यापक सामुदायिक जागरूकता बैठक आयोजित की। इस आयोजन में सदस्यों, स्वयंसेवकों, स्थानीय अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई, सभी एक सामान्य लक्ष्य से एकजुट हुए: सड़क सुरक्षा जागरूकता को कार्रवाई योग्य व्यवहार में बदलना।

बैठक का मूल संदेश स्पष्ट था: "Action speaks louder than words." "कार्य शब्दों से अधिक ज़ोर से बोलता है।"

इस बात पर जोर दिया गया कि हालांकि जागरूकता अभियान महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर उन्हें सड़कों पर व्यावहारिक रूप से लागू नहीं किया जाता है तो उनका प्रभाव काफी कम हो जाता है। इस भावना को विभिन्न हितधारकों द्वारा प्रतिध्वनित किया गया, जिन्होंने प्रासंगिक अधिकारियों की देखरेख में सड़क के किनारे जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता पर बल दिया।

हाइलाइट किए गए प्रमुख मुद्दों में से एक बुनियादी यातायात नियमों का पालन करने का महत्व था जैसे कि स्टॉपिंग लाइन पर रुकना और ज़ेबरा क्रॉसिंग का उपयोग करना। इन नियमों के बारे में व्यापक जानकारी के बावजूद, अनुपालन कम है। फाउंडेशन ने बताया कि केवल इन नियमों को जानना पर्याप्त नहीं है; ड्राइवरों और पैदल यात्रियों को समान रूप से इनका लगातार अभ्यास करना चाहिए।

बैठक में नाबालिगों द्वारा कार या बाइक चलाने के खतरनाक मुद्दे पर भी चर्चा की गई। कानून ऐसे अपराधों के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना लगाता है, फिर भी प्रवर्तन ढीला है। हाल की घटनाएं, जैसे कि पुणे में एक नाबालिग ड्राइवर के साथ हुई दुखद दुर्घटना, सख्त जांच और मजबूत प्रवर्तन की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। हितधारकों ने नाबालिगों और उनके परिवारों दोनों को एक मजबूत संदेश भेजने के लिए उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ अधिक लगातार जांच और कड़ी कार्रवाई का आह्वान किया।

प्रतिभागियों ने सख्त प्रवर्तन के साथ जागरूकता अभियान को जोड़ते हुए सड़क सुरक्षा के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की वकालत की। यह भी शामिल है:

सड़क किनारे लगातार जागरूकता अभियान: स्वयंसेवकों और सदस्यों को व्यस्त चौराहों और सड़कों के किनारे नियमित अभियान चलाना चाहिए, ड्राइवरों और पैदल चलने वालों को यातायात नियमों और सुरक्षित प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना चाहिए। वैधता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए इन अभियानों को स्थानीय अधिकारियों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

स्थानीय अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी: स्थानीय पुलिस और यातायात प्रबंधन एजेंसियों को इन जागरूकता अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, वास्तविक समय पर प्रवर्तन प्रदान करना चाहिए और यातायात नियमों के पालन के लिए उदाहरण स्थापित करना चाहिए।

सामुदायिक सहभागिता: सड़क सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ सहभागिता। इसमें कार्यशालाओं का आयोजन करना, शैक्षिक सामग्री वितरित करना और विशिष्ट स्थानीय सड़क सुरक्षा मुद्दों के समाधान के लिए इंटरैक्टिव सत्र आयोजित करना शामिल है।

वास्तविक समय प्रवर्तन: यह सुनिश्चित करना कि यातायात उल्लंघनों के लिए दंड केवल सैद्धांतिक नहीं हैं बल्कि वास्तव में लागू किए गए हैं। यादृच्छिक निरीक्षण और चौकियों सहित नियमित जांच और संतुलन, उल्लंघनकर्ताओं को पकड़ने और यातायात कानूनों की गंभीरता को मजबूत करने में मदद कर सकता है।

सफल मामलों को उजागर करना: ऐसे उदाहरणों को प्रदर्शित करना जहां सख्त कार्यान्वयन से सड़क सुरक्षा में सुधार हुआ है, प्रेरणा के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में काम कर सकता है। बेहतर अनुपालन को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की सफलता की कहानियाँ साझा की जा सकती हैं।

रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन और परिवहन विशेष ने दोहराया कि सड़क सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है। व्यक्तिगत नागरिकों से लेकर बड़ी प्रवर्तन एजेंसियों तक प्रत्येक हितधारक की भागीदारी महत्वपूर्ण है। जागरूकता को कार्रवाई में बदलकर, हम सुरक्षित सड़कें बना सकते हैं और अनावश्यक त्रासदियों को रोक सकते हैं।

बैठक कार्रवाई के आह्वान के साथ समाप्त हुई: न केवल जागरूकता फैलाना जारी रखें बल्कि यह सुनिश्चित करें कि यह जागरूकता सुसंगत, व्यावहारिक अनुप्रयोग में तब्दील हो। समन्वित प्रयासों और प्रवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी हासिल की जा सकती है।

अखिल भारतीय स्तर पर सड़क सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए आगामी परियोजनाओं और पहलों में भाग लेने के लिए सड़क सुरक्षा स्वयंसेवकों को भी आमंत्रित किया जा रहा है।

डॉ अंकुर शरण, राष्ट्रीय मुख्य परिवहन एवं योजना अधिकारी
Road Safety Omni Foundation
roadsafetysquad@gmail.com

इलेक्ट्रिक वाहन: बाधाओं के बावजूद कई वजहों से भारत में ईवी का भविष्य बेहतर, मजबूत सहयोगी तंत्र जरूरी

परिवहन विशेष न्यूज

अगर हम वाकई देश में ई-वाहन क्रांति लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मजबूत सहयोगी तंत्र भी जरूरी है। लगातार विज्ञापन, कर प्रोत्साहन जैसी सरकारी योजनाएं और सुलभ बुनियादी ढांचा निश्चित रूप से भारत में ईवी को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इन पर अभी काम होना बाकी है।

नईदिल्ली। पिछले कुछ वर्षों से भारत में कार खरीदारी में बदलाव आ रहा है और लोग पेट्रोल-डीजल के प्रभुत्व वाले बाजार से इलेक्ट्रिक वाहनों के नए ब्रांड की तरफ रुख कर रहे हैं। पिछले साल 15 लाख इलेक्ट्रिक कारें बेची गईं। समकालीन उपभोक्ताओं की चाहत और जलवायु परिवर्तन को लेकर नए उत्साह के साथ भारत का खुदरा कार बाजार इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को खरीदने और उसे प्रोत्साहित करने के नए चलन को अपना रहा है। लेकिन यह प्रवृत्ति उभरी कैसे और अचानक क्यों जोर पकड़ रही है- यह जानने के लिए भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की क्रांति पर गहराई ने नजर डालने की जरूरत है।

इसके दो कारण हैं। पहला, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर वास्तविक जागरूकता, जो वैसे समृद्ध उपभोक्ताओं को आकर्षित करता है, जो पर्यावरण हितैषी वाहन खरीदने पर ज्यादा पैसा खर्च करने को तैयार हैं। हालांकि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों और बजट के प्रति जागरूक मध्यम वर्ग भी ईवी क्रांति का लाभ उठा रहा है। टाटा जैसी कार कंपनियों ने ऐसे उपभोक्ताओं की जरूरत को समझा है और इसे पूरा करने के लिए कम लागत वाली टियागो लॉन्च की है। वे ईवी के प्रति बढ़ती दिलचस्पी को लेकर आशान्वित भी हैं। उन्होंने गुरुग्राम में सिर्फइलेक्ट्रिक वाहन का शोरूम खोला है और ईसीई वाहन और इलेक्ट्रिक वाहन के सेल्स (विक्रय विभाग) को अलग कर दिया है।

मैं पिछले महीने से किफायती ईवी की तलाश कर रही हूं। उनकी संख्या कम है। यदि आपके पास खर्च करने के लिए ज्यादा रुपये हैं, तो कई विकल्प हैं, लेकिन यदि आप अपना बजट 10 लाख रुपये तक ही रखना चाहते हैं, तो विकल्प सीमित हो जाएंगे। और यह कमी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के बजाय हतोत्साहित करेगी। सरकार ने सभी तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दी है। मेरे मित्र राजीव तुली ई-रिक्शा के व्यवसाय में हैं और इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। भले ही सुनने में अटपटा लगे, लेकिन जलवायु परिवर्तन और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के दौर में ई-वाहन एक अनिवार्यता है। निर्माताओं को किफायती मूल्य में इस मांग को पूरी करने पर ध्यान देने की जरूरत है।

एक अन्य मुद्दा, पेट्रोल पंप की तुलना में चार्जिंग स्टेशन की कमी है। चार्जिंग स्टेशन के विकास पर जोर दिए बिना ई-वाहन भारतीय मोटर चालकों के लिए सपना ही रहेगा। यहां तक कि मुझ जैसे लोगों के लिए भी, जो ईवी को अपनाना चाहते हैं। शुरुआत में एक अकेली महिला चालक के लिए बैटरी चार्जर के बिना ई-वाहन खरीदकर फंसे रहना दुस्वप्न जैसा है। इन चुनौतियों के बावजूद, मैकिंजे एंड कंपनी के अध्ययन से पता चलता है कि लोग नई कार खरीदते समय पर्यावरण की सततता पर विचार करते हैं, जो सकारात्मक है। इसके अलावा, सरकार के वाहन प्रदूषण नियंत्रण के नियम लोगों को हरित विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं।

ईवी, जो अपने शून्य-उत्सर्जन और नवीकरणीय अनुकूलता के लिए जाने जाते हैं, इस मानदंड पर खरे उतरते हैं। ईवी का रखरखाव सामान्यतः पारंपरिक वाहनों की तुलना में बहुत कम है, जो ग्राहकों के खर्च में कमी लाकर पसंदीदा विकल्प बन जाता है। ईवी पहले से ही अर्ध-स्वचालित है और निकट भविष्य में यह पूरी तरह स्वचालित होने वाला है। भारत में तेजी से इलेक्ट्रिक और हाईब्रिड वाहनों को अपनाने और विनिर्माण (फेम) ने ईवी अपनाने की प्रवृत्ति में इजाफा किया है। प्रोत्साहन आधारित सब्सिडी योजना ईवी अपनाने और उनके बुनियादी ढांचे के विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2030 तक देश में परिवहन सुविधाओं को 30 फीसदी तक इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना है। यह वित्तीय प्रोत्साहन निर्माताओं और खरीदारों, दोनों की मदद करता है। फेम के दूसरे चरण में सरकार का लक्ष्य देश भर में 2,700 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना है। हालांकि, अब भी बहुत से भारतीय कार खरीदते वक्त इलेक्ट्रिक कार के प्रति संदेह में रहते हैं। सबसे बड़ी कमी बुनियादी ढांचे की है। हालांकि फेम इस अंतर को पाटने का वादा करता है। किंतु भारतीय ऐसी चीजों में निवेश से हिचकते हैं, जो जल्दी उपलब्ध हो भी सकती है और नहीं भी। जब तक बुनियादी ढांचा विकसित नहीं हो जाता, पारंपरिक वाहनों की तुलना में ईवी को चुनने की संभावना कम है।

इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के फलने-फूलने और बनाए रखने के लिए मजबूत सहयोगी तंत्र जरूरी है। यद्यपि कर छूट, प्रोत्साहन और पर्याप्त जागरूकता है, पर सबसे बड़ी बाधा उस आबादी को समझाना है, जो यथास्थिति बनाए रखने को प्राथमिकता देती है। जलवायु कार्रवाई को लेकर जागरूकता बढ़ी है, फिर भी यह कहना मुश्किल है कि देश के लोग स्थिति की गंभीरता को समझते हैं और तत्काल कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अब बड़े पैमाने पर ई-वाहन विज्ञापनदाता भी मानते हैं कि कार चलाने वाली आबादी कुछ हद तक जलवायु कार्यकर्ता हैं, यदि नहीं भी हैं, तो वे इस दिशा की ओर अग्रसर हैं। इसलिए उनके विज्ञापनों का असर काफी कम है, जहां समाज का नवप्रवर्तक व उत्साही वर्ग (समृद्ध लोग) ईवी की ओर बढ़ रहा है।

पर्यावरण पाठशाला : विश्व कछुआ दिवस: हमारे सर्वोत्तम हरित मित्र

प्रत्येक वर्ष 23 मई को, हम विश्व कछुआ दिवस मनाते हैं, जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में कछुओं की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में सम्मान और जागरूकता बढ़ाने के लिए एक समर्पित अवसर है। 2000 में अमेरिकी कछुआ बचाव द्वारा शुरू किया गया यह दिन पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में कछुओं के महत्व और इन प्राचीन प्राणियों को उनके सामने आने वाले बढ़ते खतरों से बचाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

कछुओं का पारिस्थितिक महत्व

कछुए, अपने अद्वितीय जैविक और पारिस्थितिक गुणों के साथ, विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों, विशेष रूप से समुद्री और मीठे पानी के वातावरण के लिए अपरिहार्य हैं। यहां कुछ प्रमुख कारण बताए गए हैं कि कछुए क्यों महत्वपूर्ण हैं:

समुद्री स्वास्थ्य और प्रवाल भित्तियाँ: समुद्री कछुए, विशेष रूप से हरे समुद्री कछुए, समुद्री घास के बिस्तरों और प्रवाल भित्तियों के स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। समुद्री घासों को चरकर, वे क्यारियों की उत्पादकता को बनाए रखने में मदद करते हैं। यह, बदले में, व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछली प्रजातियों सहित असंख्य समुद्री जीवन का समर्थन करता है।

पोषक तत्व चक्रण: कछुए जलीय और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र दोनों में पोषक तत्व चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, समुद्र तटों पर जमा समुद्री कछुओं के अंडे तटीय वातावरण में आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, वनस्पति विकास का समर्थन करते हैं और तटरेखाओं को स्थिर करते हैं।

जैव विविधता समर्थन: शिकारी और शिकार दोनों के रूप में, कछुए खाद्य जाल का अभिन्न अंग हैं। वे उन प्रजातियों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं जिन पर वे भोजन करते हैं, जैसे कि जेलीफ़िश, और शार्क और शिकार के पक्षियों जैसे शिकारियों के लिए भोजन प्रदान करते हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य के संकेतक: कछुओं को अक्सर जैव संकेतक माना जाता है। उनकी उपस्थिति और स्वास्थ्य उनके आवास की स्थिति को दर्शाते हैं। कछुओं की घटती आबादी बिगड़ती पर्यावरणीय स्थितियों का संकेत दे सकती है, जो व्यापक पारिस्थितिक मुद्दों के समाधान के लिए शीघ्र हस्तक्षेप को प्रेरित करती है।

कछुओं का सामना करने वाले खतरे

उनके महत्व के बावजूद, कछुओं को कई खतरों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण उनकी आबादी में महत्वपूर्ण गिरावट आई है:

पर्यावास का विनाश: शहरीकरण, वनों की कटाई, और तटीय विकास महत्वपूर्ण घोंसले बनाने और भोजन करने वाले आवासों को नष्ट कर देते हैं।

प्रदूषण: प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव और रासायनिक संदूषक कछुओं के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं, जिससे चोटें आती हैं, हानिकारक पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है और आवास की गुणवत्ता में कमी आती है।

जलवायु परिवर्तन: बढ़ता तापमान कछुओं के घोंसले वाले स्थानों को प्रभावित करता है, विशेष रूप से बच्चों के लिंग अनुपात को, जो तापमान पर निर्भर है, संभावित रूप से विषम आबादी का कारण बनता है।

अवैध शिकार और अवैध व्यापार: कछुओं का शिकार उनके मांस, कवच और पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग के लिए किया जाता है, जिससे कुछ प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर पहुँच जाती हैं।

प्लास्टिक का उपयोग कम करें: कछुओं के निगलने या मलबे में फंसने के जोखिम को कम करने के लिए प्लास्टिक कचरे को कम करें। समुद्र तट की सफ़ाई में भाग लें और प्लास्टिक-मुक्त पहल की वकालत करें।

हमारे हरित मित्रों की रक्षा करना

कछुओं की आबादी की सुरक्षा और संरक्षण के प्रयास बहुआयामी हैं और इसके लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। यहां कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे हम योगदान दे सकते हैं:

संरक्षण कार्यक्रमों का समर्थन करें: कछुआ संरक्षण के लिए समर्पित संगठनों के साथ जुड़ें और उनका समर्थन करें। ये समूह आवासों की रक्षा करने, आबादी की निगरानी करने और घायल कछुओं के पुनर्वास के लिए जमीन पर काम करते हैं।

प्लास्टिक का उपयोग कम करें: कछुओं के निगलने या मलबे में फंसने के जोखिम को कम करने के लिए प्लास्टिक कचरे को कम करें। समुद्र तट की सफ़ाई में भाग लें और प्लास्टिक-मुक्त पहल की वकालत करें।

सतत प्रथाओं को बढ़ावा दें: टिकाऊ मछली पकड़ने की प्रथाओं और जिम्मेदार पर्यटन को प्रोत्साहित करें जो कछुओं के आवासों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं या घोंसले के शिकार स्थलों को परेशान नहीं करते हैं।

जागरूकता बढ़ाएँ: कछुओं के महत्व और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में दूसरों को शिक्षित करें। जागरूकता फैलाने और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग करें।

कछुए, जिन्हें अक्सर हमारे पानी के दिग्गज कहा जाता है, वास्तव में हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। उनका अस्तित्व हमारे पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम विश्व कछुआ दिवस मनाते हैं, आइए उनके अमूल्य योगदान को पहचानें और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन उल्लेखनीय प्राणियों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हों। कछुओं की सुरक्षा करके, हम न केवल अपनी प्राकृतिक विरासत के एक हिस्से को संरक्षित कर रहे हैं, बल्कि उस पारिस्थितिकी तंत्र के निरंतर संतुलन और स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित कर रहे हैं जिस पर हम सभी निर्भर हैं।

E-mail:
indiangreenbuddy@gmail.com

इनसाइड

फीमेल ऑर्गेज्म से जुड़े हैं ये 5 अज्ञात फैक्ट्स, जानकर आप भी हो जाएंगी हैरान

महिलाओं के शरीर से जुड़े फैक्ट्स महिलाओं को खुद पता नहीं होते हैं. उन्हें अपने शरीर के बारे में समझने की जरूरत है, खुलकर बात करने की जरूरत है, न की इस पर चुप रहने की. सेक्स जरूरी है और इससे जुड़े अंग जो आपको उत्तेजित करते हैं उसके बारे में जानना भी जरूरी है. आज हम 5 ऐसे ही अज्ञात तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आपको हैरानी होने वाली है'

महिलाओं में 3 से अधिक यौन अंग होते हैं !

महिला के बाहरी यौन अंग को लेबिया मेजोरा कहा जाता है. यह योनि के खुलने के आसपास वाली त्वचा होती है, जो 2 फोल्ड्स में मौजूद होती है. भीतरी यौन अंग को लेबिया माइनोरा कहा जाता है, जो लेबिया मेजोरा के नीचे स्थित होते हैं. आंतरिक महिला यौन अंग में अंडाशय (Ovaries), फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय (Uterus), गर्भाशय ग्रीवा (Cervix) और योनि (Vagina) हैं. महिला सेक्स सिर्फ प्रजनन (Reproductive) अंग नहीं हैं, वे महिलाओं में यौन उत्तेजना का भी काम करते हैं.

विभिन्न चरणों में समझे फीमेल ऑर्गेज्म

जिस तरह से एक महिला को ऑर्गेज्म प्राप्त होता है वह पुरुषों की तुलना में अलग होता है. पहले एक उत्तेजना चरण होता है जो शारीरिक प्रतिक्रियाओं से प्रेरित होता है. दूसरा जब क्लाइटोरिस प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है. क्लाइटोरिस को "फीमेल पेनिस" भी कहते हैं, जो महिलाओं के शरीर का सबसे ज्यादा उत्तेजित करने वाला अंग माना गया है. तीसरा चरण ऑर्गेज्म से ठीक पहले होता है जहां हृदय गति सबसे अधिक होती है. अंतिम चरण रिलीज या संभोग का चरण है.

क्लाइटोरिस सबसे अधिक उत्तेजित करने वाला अंग

क्लाइटोरिस सबसे अधिक उत्तेजित करने वाला अंग इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें 8,000 से अधिक तंत्रिका हैं. इस प्रकार से यह सबसे अधिक उत्तेजना उत्प्रेरण अंगों में से एक है. ऐसा कहा जाता है कि 75 प्रतिशत से अधिक महिलाओं में क्लाइटोरिस को छूने पर ही ऑर्गेज्म चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है. तीन-चौथाई क्लाइटोरिस छिपे हुए होते हैं शायद इसीलिए इसे कामोत्तेजना वाले अंग के रूप में नहीं देखा जा सकता है. क्लाइटोरिस का एकमात्र उद्देश्य महिलाओं को आनंद देना होता है.

फीमेल ऑर्गेज्म में स्तन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

महिलाओं में स्तन और निप्पल की उत्तेजना के कारण भी ऑर्गेज्म प्राप्त किया जा सकता है. अध्ययनों से पता चला है कि निप्पल को उत्तेजित करने से भी जेनाइटल्स यानी जननांगों को सक्रिय किया जा सकता है.

महिला को आनंद देने वाले अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं

महिलाओं को सुख देने वाले अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. एक अंग से प्रत्येक अंग उत्तेजित होता है. जिस वजह से महिलाओं को अधिक आनंद की प्राप्ति होती है. पार्टनर की प्राथमिकता, पसंद और सेक्सुअल एनाटॉमी को ध्यान में रखें. इंटरकोर्स यानी संभोग के दौरान यह महत्वपूर्ण होता है.

महिलाओं में होने वाली हेल्थ से जुड़ी परेशानियां, जिनके बारे में जानना है बेहद जरूरी

पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कुछ अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स होने की संभावना अधिक रहती है लेकिन समय पर इलाज होने पर उपचार संभव है. जानिए महिलाओं में होने वाली कुछ सामान्य हेल्थ से जुड़ी परेशानियों के बारे में. क्या आप जानते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में हार्ट अटैक डेथ्स की संभावना अधिक होती हैं. यही नहीं, डिप्रेशन और एंग्जायटी की समस्या भी महिलाओं में अधिक देखी जाती है. महिलाओं और पुरुषों दोनों कई हेल्थ कंडिशंस से गुजरते हैं लेकिन कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हैं, जो महिलाओं में ज्यादा देखी जाती हैं. वहीं जानकारी की कमी या लापरवाही के कारण कई महिलाओं की हेल्थ कंडिशंस का समय पर निदान नहीं हो पाता.

बोर्ड रिजल्ट में स्कूल की टॉपर रही बेटी? आगे की पढ़ाई विदेश में, एजुकेशन लोन लेकर सफर करें आसान, जानें सबकुछ

बेटी के लिए फॉरेन एजुकेशन लोन के लिए 10 बैंकों की दरेंबेटी के लिए फॉरेन एजुकेशन लोन के लिए 10 बैंकों की दरें

अपनी बेटी को विदेश पढ़ने भेजना चाहते हैं तो इसके लिए खर्च की चिंता करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि कई बैंक हैं जो विदेश में शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन देते हैं. आइए जानें कौन से बैंक हैं जो एजुकेशन लोन दे रहे हैं और क्या ब्याज दरें हैं इनकी...

एक के बाद एक राज्यों से 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम आ रहे हैं. हर साल की तरह इस बार भी बेटियां बाजी मार रही हैं. क्या आप अपनी बेटी को विदेश पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं? या फिर बेटी 12 वीं क्लास में आई है और अगले साल के लिए आप विदेश में एजुकेशन को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं? दोनों में से कोई भी परिस्थिति हो, आपकी बेटी की आगे की पढ़ाई विदेश के किसी बेहतरीन संस्थान में हो, इसके लिए आपको विभिन्न शैक्षणिक कोशिशों के अलावा खर्च मैनेज करने का तनाव भी होगा. आइए आज जानते हैं भारत में मौजूद ऐसे एजुकेशन लोन के बारे में जो फॉरेन में पढ़ाई और प्रवास के दौरान के विभिन्न खर्चों को हैंडल करते हैं.

कम ब्याज दरों पर एजुकेशन देने वाले बैंकों की इस कैटिगरी में कई योजनाएं हैं जिन्हें अपनी जरूरत के मुताबिक चुन सकते हैं. विदेशी होम लोन के अंतर्गत आने वाले खर्चों में ट्यूशन फीस, रहने का खर्च और अन्य कई खर्चों जैसे लैपटॉप या किताबों की खरीददारी, फ्लाइट टिकट जैसे जरूरी खर्चें शामिल हैं. फॉरेन एजुकेशन लोन के लिए वित्तीय संस्थान को शॉर्टलिस्ट करते समय, स्टूडेंट्स और उनके पैरेंट्स को कई जरूरी फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए. जैसे कि कौन सा बैंक क्या ब्याज दर दे रहा है, लोन रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग की फीस और इसमें लगने वाला समय, लोन टेन्योर, प्रीपेमेंट की शर्तें आदि. (बेटी पैदा हुई है? डॉक्टर बनाना है बिटिया को तो आज से ही शुरु कर दें तैयारी, स्टेप-बाई-स्टेप गाइड)

बैंक बाजार डॉट कॉम के डाटा के मुताबिक, टॉप 10 बैंक जो सात साल की अवधि के साथ 50 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन 13.7 प्रतिशत से कम ब्याज दर के साथ देते हैं, वे ये हैं. यहां ध्यान दें कि न्यूज18 हिन्दी डिजिटल पर यह लेख केवल प्राथमिक जानकारी के लिए लिखा गया है. आप अपनी जरूरतों और क्षमता के मुताबिक आखिरी फैसला लें. सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में सारी जानकारी आप यहां क्लिक करके ले सकते हैं.

भारतीय स्टेट बैंक फॉरेन एजुकेशन लोन पर लगाया जाने वाला ब्याज 11.15 प्रतिशत से शुरू होता है. यह कई दूसरे बैंकों से थोड़ी ज्यादा है. सात साल की अवधि के लिए 50 लाख रुपये के लोन के लिए ईएमआई 86,007 रुपये होगी.

एचडीएफसी बैंक 12.50 प्रतिशत की ब्याज दर से शुरू होने वाला फॉरेन एजुकेशन लोन देता है. सात साल की अवधि वाले 50 लाख रुपये के ऋण पर ईएमआई 89,606 रुपये होगी.

इंडियन बैंक में फॉरेन एजुकेशन लोन पर 8.6 प्रतिशत से शुरू होने वाली ब्याज दरें हैं. सात साल की अवधि के लिए 50 लाख रुपये के विदेशी शिक्षा ऋण पर ईएमआई 79,435 रुपये बनती है.

एक्सिस बैंक 13.7 प्रतिशत की ब्याज दर से शुरू होने वाले फॉरेन एजुकेशन लोन प्रदान करता है जिसकी सात साल की अवधि के लिए 50 लाख रुपये के लोन पर ईएमआई 92,873 रुपये होगी.

बैंक ऑफ इंडिया विदेशी शिक्षा ऋण पर 11.85 प्रतिशत से शुरू होने वाली ब्याज दरों की पेशकश करता है। सात साल की अवधि वाले 50 लाख रुपये के ऐसे ऋण पर ईएमआई 87,863 रुपये होगी

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विदेशी शिक्षा ऋण पर 9.25 प्रतिशत से शुरू ब्याज लेता है. सात साल की अवधि के लिए 50 लाख रुपये के विदेशी शिक्षा ऋण पर ईएमआई 81,081 रुपये होगी. (महिलाओं और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए आप यहां क्लिक कर सकती हैं)

बैंक ऑफ बड़ौदा फॉरेन एजुकेशन लोन पर 9.7 प्रतिशत से शुरू होने वाली ब्याज दरों की पेशकश करता है. इसमें सात साल की अवधि के लिए 50 लाख रुपये के ऋण पर ईएमआई 82,233 रुपये होगी.

आईसीआईसीआई बैंक और पंजाब नेशनल बैंक दोनों ही बैंक फॉरेन एजुकेशन लोन पर 10.25 प्रतिशत से शुरू होने वाली ब्याज दरें लेते हैं. सात साल की अवधि के लिए 50 लाख रुपये के ऐसे ऋण पर ईएमआई 83,653 रुपये होगी. (गोल्ड लोन है कमाल की चीज ! लेकिन नहीं चुकाया तो खो बैठेंगी नानी-दादी के कंगन, हो सकती है नीलामी)

केनरा बैंक फॉरेन एजुकेशन लोन पर 10.85 प्रतिशत से शुरू होने वाली ब्याज दरों की पेशकश करता है. सात साल की अवधि के लिए 50 लाख रुपये के ऋण पर ईएमआई 85,218 रुपये होगी।

मां बनने के बाद छोटी-छोटी बातें भूलने लगी हैं, तो 'मॉमी ब्रेन' प्रॉब्लम से ऐसे करें बचाव

क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप मां बनने के बाद छोटी छोटी बातें भूलने लगीं हैं? कभी ऐसा हुआ हो कि आप कमरे में तेजी से गईं और वहां जाकर भूल गईं कि आप क्यों कमरे में आईं या गाड़ी की चाबी हाथ में हैं और आप पूरे फ्लैट में चाबी ढूंढती रहीं? अगर आप ऐसी समस्याओं से परेशान हो गई हैं तो यह अकेले आपकी ऐसी समस्या नहीं है. दरअसल इस समस्या को मॉमी ब्रेन के नाम से जाना जाता है. वेरीवेलफैमिली के मुताबिक एक स्टडी में पाया गया है कि बच्चे को जन्म देने से मां का मस्तिष्क भी काफी प्रभावित होता है और कभी-कभी लंबे समय तक इसका असर कायम रहता है. ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने भी ये पाया गया है कि मां बनने से महिला के याददाश्त क्षमता पर स्थाई असर पड़ता है.

क्या है इस परेशानी की वजह?

कई शोधकर्ताओं ने माना कि ये परिवर्तन एक नई मां को अपने बच्चे की देखभाल करने की क्षमता को बढ़ाने का एक नेचुरल तरीका होता है. यह भी कहा जा सकता है कि मस्तिष्क में ये परिवर्तन दरअसल नई माताओं को बच्चे की जरूरतों को अपनाने और उन्हें पूरा करने के लिए अहम होता है.

मॉमी ब्रेन से उबरने के उपाय

धैर्य रखें- शरीर में हुए इस बायोलॉजिकल बदलाव की वजह से आप खुद से परेशान हैं और इरिटेट हो जाती हैं आपको बता दें कि अगर आप थोड़ा धैर्य रखें और किसी भी काम को पूरा करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्लान बनाएं तो मॉमी ब्रेन की समस्या से उबर सकती हैं.

लिस्ट बनाएं- इस समस्या से बचने के लिए बेहतर होगा कि आप अपने हर काम की लिस्ट बनाएं. इसके लिए आप एक नोटबुक कैरी करें और जब भी कुछ याद आए तो उसे लिख लें. ऐसा करने से आप जरूरी चीजों को भूलेंगी नहीं.

प्लान बनाएं- आप पहले से चीजों के लिए प्लान बनाएं और अपनी हर चीज को सही जगह पर रखने की आदत डाल लें. इससे आपका काम काफी आसान बन जाएगा. मसलन, आप अगर सुबह डॉक्टर के पास जाने वाली हैं तो रात में ही सारा सामान तैयार रखें. आप चाभी, वॉलेट आदि हमेशा एक ही जगह पर रखें आदि.

पर्याप्त नींद जरूरी- नई मांओं की व्यस्तता 24 घंटे की होती है. लेकिन आपको कुछ इस तरह अपने रुटीन को फॉलो करना है कि आपकी नींद पूरी हो सके. इसके लिए आप परिवार के लोगों की मदद ले सकती हैं और बच्चे के साथ ही सोने और जागने की रुटीन को फॉलो कर सकती हैं. भरपूर नींद आपके ब्रेन को रिलैक्स करेगा और ये बेहतर तरीके से काम कर पाएगा.

ब्रेन को दें एक्स्ट्रा केयर- ब्रेन के लिए आप अपने खानपान पर ध्यान दें और ब्रेन गेम खेलें. ब्रेन गेम आपके दिमाग को एक्टिव रखने का काम करेगा और ये बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे. इसके अलावा, आप उन चीजों को डाइट में शामिल करें जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हो और भरपूर प्रोटीन हो.

प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाएं भूलकर भी न करें यह गलती, जन्म से पहले ही बच्चे का IQ हो सकता है कमजोर

प्रेग्नेंसी में महिलाएं जो भी एक्टिविटी करती हैं, उसका सीधा असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है. महिलाओं के इमोशंस से भी अजन्मे बच्चे का विकास सीधे तौर पर प्रभावित होता है. इसे लेकर एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसके बारे में प्रेग्नेंट महिलाओं को जरूर जानना चाहिए.

प्रेग्नेंट महिलाओं को स्ट्रेस से बचना चाहिए. प्रेग्नेंसी के दौरान अत्यधिक तनाव गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है. एक नई स्टडी में चेतावनी दी गई है कि प्रेग्नेंसी के आखिरी कुछ महीनों में ज्यादा स्ट्रेस लेने से जन्म से पहले ही बेबी बॉय का IQ लेवल कम हो सकता है. आईक्यू (Intelligence Quotient) किसी भी व्यक्ति की मानसिक क्षमता को जानने का स्टैंडर्ड तरीका होता है. इस रिसर्च में दिलचस्प बात यह सामने आई है कि प्रेग्नेंसी में तनाव से गर्भ में पल रहे सिर्फ बेबी बॉय का आईक्यू लेवल प्रभावित होता है, लेकिन बेबी गर्ल के आईक्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. आखिर इसकी वजह क्या होती है और तनाव किस तरह अजन्मे बच्चों का आईक्यू लेवल प्रभावित कर सकता है. इस बारे में शोधकर्ताओं ने कई बातें बताई हैं.

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेग्नेंसी के तीसरे ट्राइमेस्टर के दौरान स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल का उच्च स्तर गर्भ में पल रहे लड़कों के आईक्यू स्कोर को प्रभावित कर सकता है. शोधकर्ताओं का कहना है कि खून में कोर्टिसोल का लेवल लड़कियों के आईक्यू को प्रभावित नहीं करता है. भ्रूण के विकास के लिए कोर्टिसोल का संपर्क आवश्यक होता है, लेकिन यह नुकसान भी पहुंचा सकता है. यह एक स्टेरॉयड हार्मोन होता है, जो शरीर को तनाव का जवाब देने में मदद करता है. ऐसा माना जाता है कि प्रेग्नेंसी के दौरान मिलने वाला यह हॉर्मोन जन्म के बाद भी बच्चों के मस्तिष्क को प्रभावित करता है.

प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है और लड़कियों को जन्म देने वाली गर्भवती महिलाएं आमतौर पर लड़कों की तुलना में अधिक कोर्टिसोल रिलीज करती हैं. हालांकि प्लेसेंटा में 11बीटा-एचएसडी2 नामक एक एंजाइम कोर्टिसोल की मात्रा को नियंत्रित करता है. यह कोर्टिसोल को उसके निष्क्रिय रूप में परिवर्तित करके भ्रूण तक पहुंचता है, जिसे कोर्टिसोन कहा जाता है. स्टडी के रिजल्ट बताते हैं कि लड़कियां प्लेसेंटल 11बीटा-एचएसडी2 की गतिविधि से अधिक सुरक्षित हो सकती हैं, जबकि लड़के मैटरनल साइकोलॉजिकल कोर्टिसोल के जन्मपूर्व जोखिम के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं.

इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने तीसरे ट्राइमेस्टर वाली 943 गर्भवती महिलाओं के कोर्टिसोल और कोर्टिसोन स्तर और उनके सात वर्ष की आयु के 943 बच्चों के आईक्यू परीक्षणों पर डेटा का विश्लेषण किया था. उन्होंने पाया कि जिन गर्भवती महिलाओं के गर्भ में लड़का होता है, उनके खून में कोर्टिसोल का स्तर उन महिलाओं की तुलना में कम होता है, जिनके गर्भ में लड़की होती है. गर्भ में उच्च कोर्टिसोल स्तर के संपर्क में आने वाले लड़कों ने 7 साल की उम्र में आईक्यू टेस्ट में कम नंबर हासिल किए. हालांकि उसी उम्र की लड़कियों ने आईक्यू टेस्ट में बेहतर स्कोर किया. स्टडी की लीड ऑथर डॉ. अंजा फेंगर ड्रेयर की मानें तो गर्भावस्था के दौरान यूरिन में कोर्टिसोन के स्तर और बच्चों में आईक्यू स्कोर के बीच संबंध की जांच करने वाली यह पहली स्टडी है.

ज्यादा वजन भी बन सकता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी की वजह, इन तरीकों से करें बचाव

हाई रिस्क प्रेगनेंसी के खतरे से खुद को बचाना है तो समय-समय पर अपनी जांच जरूर कराती रहें. इसके अलावा, जहां तक हो सके प्रेगनेंसी में तनाव से दूर रहें, भरपूर आराम करें और रोजाना योग जरूर करें. इन बातों का ध्यान रखकर आप इस खतरे से बच सकती हैं.

मां बनने का सपना हर महिला देखती है. लेकिन कई महिलाओं में सेहत से जुड़ी समस्याओं की वजह से उनकी प्रेगनेंसी कठिनायों से भरी होती है. कई बार तो उनके लिए प्रेगनेंसी जोखिम भरा हो जाता है और इससे मां और पेट में पल रहे बच्चे की जान तक जा सकती है. इसी जोखिम को 'हाई रिस्क प्रेगनेंसी' कहा जाता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में तकरीबन 5,29,000 महिलाओं की मौत गर्भावस्था के दौरान इन खतरों की वजह से हो जाती है. इसकी वजह खराब सेहत, बदलती लाइफस्टाइल, खान पान में लापरवाही को माना जाता है. यही नहीं, कई बार ऐसी समस्याएं किसी बीमारी या जेनेटिक डिजीज की वजह से भी हो सकती है.

हाई रिस्क प्रेगनेंसी की ये हैं बड़ी वजह

एनआईएच के मुताबिक अगर महिला को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज है या वो एचआईवी पॉजिटिव है तो उसे प्रेगनेंसी में रिस्क की समस्या हो सकती है. अगर महिला का वजन ज्यादा है तो इससे हाई ब्लड प्रेशर, प्रीक्लेम्पसिया, गर्भकालीन मधुमेह, स्टिलबर्थ, न्यूरल ट्यूब दोष और सिजेरियन डिलीवरी की समस्या हो सकती है. इसकी वजह से जन्म के समय नवजात में हृदय रोग का खतरा 15% तक बढ़ सकता है.

किशोरावस्था और 35 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं में गर्भावस्था की वजह से प्रीक्लेम्पसिया और गर्भकालीन उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी की वजह बन सकता है. गर्भाशय में हुई कोई पुरानी सर्जरी की वजह से भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी का खतरा हो सकता है. इसके अलावा, जुड़वा बच्चों और आईवीएफ द्वारा गर्भ धारण की प्रक्रिया भी महिलाओं में रिस्की प्रेगनेंसी की वजह हो सकता है.

हाईरिस्क प्रेगनेंसी से बचाव का तरीका

अगर आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी से बचना चाहती हैं तो समय-समय पर अपनी जांच कराती रहें. इसके अलावा, प्रेगनेंसी में तनाव से बचें, भरपूर आराम करें, रोजाना योग ध्यान करें, फ्रेश हवा में वॉक पर जाएं, हेल्दी खान पान करें और डॉक्टर की संपर्क में रहें.

'मैं इस्तीफा नहीं दूंगी...', आप सांसद स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा सीट छोड़ने से किया इनकार

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वतंत्र और निष्पक्ष पुलिस जांच वाले बयान पर AAP राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा उन्होंने अदालत के बाहर ट्रायल कर दिया और मुझे दोषी मान लिया। पूरी पार्टी मुझे दोषी करार करने में लगी है। वे कैसे कह सकते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो? हर दिन कुछ छेड़छाड़ किए गए वीडियो कुछ छेड़छाड़ किए गए सीसीटीवी फुटेज डालते हैं।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को कहा कि अगर किसी को उनकी राज्यसभा सीट चाहिए होती तो भी वह स्वेच्छा से सीट दे देतीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब चाहे दुनिया की कोई भी शक्ति लग जाए, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। मुझ पर इस्तीफा देने का दबाव डाला जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 'स्वतंत्र और निष्पक्ष पुलिस जांच' वाले बयान पर AAP राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा, ₹उन्होंने अदालत के बाहर ट्रायल कर दिया और मुझे दोषी मान लिया। पूरी पार्टी मुझे दोषी करार करने में लगी है। वे कैसे कह सकते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो? हर दिन कुछ छेड़छाड़ किए गए वीडियो, कुछ छेड़छाड़ किए गए सीसीटीवी फुटेज डालते हैं। कभी कहते हैं कि मैं भाजपा की एजेंट हूं, कभी चरित्र हनन करते हैं, कभी धमकाते हैं। ऐसे में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कैसे होगी?

'भाजपा का एजेंट करार देने की दी धमकी'

मारपीट मामले में शिकायत दर्ज करने में देरी पर स्वाति मालीवाल ने कहा, ₹मुझे बोला गया था कि अगर तुमने शिकायत दर्ज की। पार्टी मुझे भाजपा का एजेंट करार देगी। घटना के बाद जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंची, तो मैं SHO के सामने बहुत रो रही था। उस समय जब मैंने अपने फोन पर मीडिया के कई कॉल देखे, मैं इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहती थी। इसके बाद पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मेरे घर आए और मुझे कहा गया कि पार्टी इस मामले में कार्रवाई करेगी।

संजय सिंह मेरे आवास पर आए और बात की: स्वाति

उन्होंने कहा कि संजय सिंह मेरे आवास पर आए थे। उन्होंने बिभव से भी बात की। उसके बाद अगले दिन उन्होंने स्वीकार किया कि स्वाति के साथ मारपीट हुई और अरविंद जी संज्ञान ले रहे हैं। अगले ही दिन हम सभी ने बिभव कुमार को इन लोगों के साथ लखनऊ में दिखा। मुझे बोला गया था कि अगर तुमने शिकायत दर्ज की। पार्टी मुझे भाजपा का एजेंट करार देगी।

'जब मुझ पर हमला हुआ था तो CM केजरीवाल अपने घर पर थे मौजूद', स्वाति मालीवाल का दावा

आप के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार ने उन पर हमला किया था। उन्होंने दावा किया कि बिभव कुमार ने उनकी छाती पेट और निजी अंगों में लात मारी थी और बेरहमी से उन्हें घसीटा और उनकी कमीज ऊपर खींची थी। उस वक्त सीएम केजरीवाल वहीं मौजूद थे।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने एक साक्षात्कार में 13 मई को मुख्यमंत्री आवास में उनके साथ हुई आपबीती बताई। उन्होंने बताया कि जब मुख्यमंत्री के सहयोगी बिभव कुमार ने उन पर हमला किया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां मौजूद थे। मालीवाल की ओर से ये प्रतिक्रिया उनपर हुए हमले पर अरविंद केजरीवाल की पहली सीधी प्रतिक्रिया के बाद आई है। उनकी इस प्रतिक्रिया से राजनीतिक हलचल पैदा हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वाति पर हुए हमले को लेकर कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी और न्याय मिलेगा।

बिभव ने उनकी छाती पर हमला किया

स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार ने उन पर हमला किया था। उन्होंने दावा किया कि बिभव कुमार ने उनकी छाती, पेट और निजी अंगों में लात मारी थी और बेरहमी से उन्हें घसीटा और उनकी कमीज ऊपर खींची थी। उन्होंने घटना को विस्तार से बताते हुए कहा कि वो 13 मई को सुबह करीब नौ बजे केजरीवाल के आवास पर गई थी। वहां पर मौजूद कर्मचारी ने उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाया और कहा कि केजरीवाल वहीं पर उनसे मिलने आएंगे। तब तक बिभव कुमार कमरे में आ गए। बिभव को देखकर उन्होंने पूछा कि अरविंद जी मुझसे मिलने आ रहे थे, मामला क्या है।

बिभव ने उन्हें लात मारना शुरू किया

स्वाति ने बताया कि इतना कहने के बाद बिभव ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। सात-आठ थप्पड़ मारे, जब उन्होंने उसे धक्का देने की कोशिश की, तो उसने उनके पैर पकड़ लिए और जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने बताया कि जमीन पर गिरते ही बिभव ने उन्हें लात मारना शुरू कर दिया। इसके बाद वो मदद के लिए चीखी पर कोई मदद के लिए नहीं आया। इस सवाल पर कि क्या बिभव को उन्हें पीटने का निर्देश दिया गया था, स्वाति ने कहा ये जांच का विषय है कि क्या उसने खुद ऐसा किया या उसे ऐसा करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने कहा कि मैं जांच में सहयोग कर रही हूं और किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि मुझे पीटा जा रहा था और अरविंद केजरीवाल वहां थे।

कभी पद की लालसा नहीं रही: मालीवाल

किसी अधिवक्ता के लिए राज्यसभा सीट खाली करने पर आम आदमी पार्टी के साथ उनकी असहमति के सवाल पर स्वाति ने कहा कि अगर मुझसे विनम्रता से पूछा गया होता, तो मैं अपनी जान दे देती। सांसद पद बहुत छोटी सी बात है। अगर आप मेरे पूरे करियर को देखेंगे तो पाएंगे कि मुझे कभी भी किसी पद की लालसा नहीं रही। मैंने 2006 में अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी और केजरीवाल के साथ जुड़कर जमीनी स्तर पर काम किया।

दिल्ली हरियाणा समेत 8 राज्यों की 58 सीटों पर 25 मई को चुनावी दंगल में 2 ट्रांसजेंडर भी है शामिल

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में देश की 58 लोकसभा सीटों पर होने वाले मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसके लिए चुनाव प्रचार की मारधाड गुरूवार 23 मई को थम जाएगा।इन सीटों पर शनिवार 25 मई को वोटिंग डाले जाएगे। दिल्ली की 7 सीटों पर 2 ट्रांसजेंडर भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहीं है। नॉर्थ वेस्ट से ट्रांसजेंडर कैंडीडेट पूजा और दक्षिण दिल्ली से ट्रांसजेंडर प्रत्यक्षी राजन सिंह ताल ठोक रही हैं।बता दें कि दिल्ली में करीब 1.52 करोड वोटर्स है।जिनमें 1228 थर्डजेंडर वोटर्स है।

पुरूष 82.13 लाख और 69.88 लाख महिला वोटर्स है। 29 वर्षीय पूजा नरेला की निवासी है। ट्रांसजेंडर कैंडीडेट के मेनिफेस्टो में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने,हर ट्रेन में दो अतिरिक्त जनरल डिब्बे जोडने ,पैट्रोल-डीजल को 50 रूपये करने,अस्पताल में मरीज की मौत होने पर पूरा बिल माफ करने के अलावा दलित-पिछडीञजाति को समान अधिकार दिलवाने का वादा कर रही है। ट्रांसजेंडर पूजा भारतीय जन जागृति पार्टी की उम्मीदवार है तो वही किन्नर राजन सिंह 26 साल बतौर निर्दलीय प्रत्यक्षी है।

छठे चरण की 58 सीटो का विवरण इस प्रकार है:- बिहार-8 कुल प्रत्यक्षी-86,हरियाणा-10 कुल कंडीडेट-223, झारखंड-4कुल प्रत्यक्षी-93, ओडिशा-6 कुल उम्मीदवार-64, उत्तर प्रदेश-14,कुल प्रत्यक्षी-162, पश्चिम बंगाल-8,कुल प्रत्यक्षी-79 है। तो वहीं एनसीटी दिल्ली में -7, कुल-162 प्रत्यक्षी है ।जम्मू-कश्मीर में 1 सीट के लिए कुल प्रत्यक्षियों की संख्या -20 है। इस तरह कुल राज्य -8 की 58 सीटें और कुल कैंडीडेटों की संख्या-889 है।

उल्लेखनीय है कि पहले चरण फेज में देशभर के 21 राज्यों की कुल-102 सीटों पर वोट डाले जा चुके है। जबकि दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग हो चुकी है। इसी क्रम में तीसरे चरण में-11राज्यों की 93 सीटों पर मतदान हो गए हैं।जबकि पांचवे चरण में 8 राज्यों की कुल 49 सीटों पर 20 मई को वोटिंग डाले जा चुके है। अब इसी कडी में शनिवार 25 मई को छठवें चरण मे 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएगे। इसके बाद आखिरी फेज 1 जून को होगा। इसमें 8 राज्यो में 57 सीटों पर 904 उम्मीदवार खडे हैं। परिणाम 4 जून को कुल 543 लोकसभा सीटों के चुनाव परिणाम घोषित किए जाएगें।

दिल्ली में थमा चुनाव प्रचार का शोर, आखिरी दिन BJP-AAP-कांग्रेस ने झोंकी पूरी

परिवहन विशेष न्यूज

भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी ने 18 मई को उत्तर पूर्वी व 22 मई को पश्चिमी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर चुके हैं। अमित शाह भी दक्षिणी दिल्ली में चुनावी सभा को संबोधित किए थे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी दो लोकसभा सीटों पर जनसभा को संबोधित किया। वहीं सोनिया गांधी ने भी वोटरों से INDIA गठबंधन को वोट करने की अपील की।

नई दिल्ली। दिल्ली में 25 मई को मतदान होगा। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था। गुरुवार को राजधानी में तीनों दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। इसके साथ ही शाम से प्रचार का शोर थम गया। आखिरी दिन प्रत्याशी और कार्यकर्ता घर-घर में जाकर लोगों से संपर्क साधा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी। पार्टी के बड़े नेताओं ने दिल्ली के अलग-अलग स्थानों पर चुनाव प्रचार किया।

भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 18 मई को उत्तर पूर्वी व 22 मई को पश्चिमी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी दक्षिणी दिल्ली में चुनावी सभा को संबोधित किए थे। पार्टी के अन्य बड़े नेता व केंद्रीय मंत्री दिल्ली में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के साथ रोड शो कर चुके हैं। बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, स्मृत इरानी सहित अन्य बड़े नेता अंतिम चुनाव प्रचार में उतरे।

भाजपा के इन नेताओं ने किया प्रचार

केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल पश्चिमी दिल्ली में किया रोड शो।

केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी चांदनी चौक और पूर्वी दिल्ली में रोड शो किया।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देंवेंद्र फड़णवीस उत्तर पूर्वी दिल्ली में रोड शो किया।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने नई दिल्ली में रोड शो किया।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली में रोड शो किया।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने चांदनी चौक में व्यापारियों के साथ बैठक की।

राहुल गांधी ने दो सीटों पर की जनसभा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली सीट और उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट पर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार कन्हैया कुमार, जेपी अग्रवाल और उदित राज मौजूद रहे। राहुल गांधी ने मंगोलपुरी में महिलाओं के साथ विचार-विमर्श किया। वहीं राहुल ने लोगों के साथ जुड़ने के लिए दिल्ली मेट्रो में भी सफर किया।

सोनिया गांधी ने दिल्ली की जनता से की अपील

सोनिया गांधी ने अपने संबोधन में कहा- मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यह चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण जैसे मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। आपको इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभानी है। आपका हर एक वोट रोजगार बनाएगा, महंगाई कम करेगा, महिलाओं को सशक्त करेगा और एक सुनहरे भविष्य में समता और बराबरी का भारत बनाएगा। मैं आपसे अपील करती हूं कि कांग्रेस व आइएनडीआइ गठबंधन के प्रत्याशियों को दिल्ली की सातों सीटों पर भारी मतों से विजयी बनाइए।

अब वोटिंग करने में दिल्लीवासियों को नहीं होगी परेशानी, बूथ पर कूलर और ठंडे पेयजल सहित ये सुविधाएं मिलेगी

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के अधिकारी मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान पर भी पूरी नजर रख रहे हैं। चुनाव के दिन के लिए मौसम विभाग द्वारा पहले जारी रेड अलर्ट के आरेंज अलर्ट में तब्दील होने इस बात की उम्मीद जग्गी है कि तापमान 45-46 डिग्री की जगह थोड़ा कम रहेगा। इससे अधिकारियों ने थोड़ी राहत की सांस ली है।

नई दिल्ली। राजधानी में चुनाव आयोग मतदान बढ़ाने के लिए भीषण गर्मी को मात देने की तैयारियों में जुटा हुआ है। इसलिए दिल्ली के मतदान केंद्रों पर टेंट व शेड लगाकर छायादार बनाया जा रहा है। साथ ही मतदान केंद्रों पर कूलर व मिस्ट फैन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर ठंडे पेयजल के लिए वाटर कूलर व मिट्टी के घड़े की व्यवस्था की गई है। इसलिए मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर घड़े का पानी भी पीने के लिए मिलेगा।

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के अधिकारी मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान पर भी पूरी नजर रख रहे हैं। चुनाव के दिन के लिए मौसम विभाग द्वारा पहले जारी रेड अलर्ट के आरेंज अलर्ट में तब्दील होने इस बात की उम्मीद जग्गी है कि तापमान 45-46 डिग्री की जगह थोड़ा कम रहेगा। इससे अधिकारियों ने थोड़ी राहत की सांस ली है।

मतदान बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयास

सीईओ कार्यालय के अधिकारी कहते हैं कि गर्मी के कारण मतदान कम न होने पाए इसके लिए पूरे जोर शोर से प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि मुंबई में मतदान केंद्रों पर गर्मी में अधिक देर तक लाइन में लगने के कारण बहुत मतदाता बगैर मतदान के घर वापस लौट गए थे।

सीईओ कार्यालय इस प्रयास में जुटा है कि दिल्ली में ऐसी स्थिति न होने पाए। इसलिए सीईओ कार्यालय तैयारियों की पूरी निगरानी कर रहा है। दिल्ली में 2627 जगहों पर 13,641 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ज्यादातर मतदान केंद्र स्कूलों में बनाए गए हैं।

सभी मतदान लोकेशन का निरीक्षण किया गया

सीईओ कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी मतदान लोकेशन का निरीक्षण किया गया है। 2400 स्कूलों में पहले से वाटर कूलर है। जिन मतदान केंद्रों में पहले से वाटर कूलर नहीं है वहां भी वाटर कूलर लगाए जा रहे हैं। इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि जिस जगह मतदाता वोट देने के लिए लाइन में लगेंगे वहां भी छाया रहे। सभी मतदान केंद्र पर वेटिंग एरिया होगा, जहां मतदाताओं के बैठने की सुविधा होगी।

DU कैंपस की दीवारों पर लिखे मिले विवादित नारे, पुलिस में की गई शिकायत; इस संगठन ने ली जिम्मेदारी

डीयू के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की दीवारों पर नारे लिखे गए हैं। इनमें चुनाव बहिष्कार करो नक्सलबाड़ी जिंदाबाद जैसे नारे लिखे गए हैं। नारों के पीछे भगत सिंह छात्र एकता मंच का नाम लिखा गया है। मंच ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली है। इससे पहले डीयू के कई कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी हालांकि जांच में कुछ भी नहीं मिला।

नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में भी विवादित नारे लिखे गए हैं। इनमें चुनाव बहिष्कार करने की अपील की गई है। नारे लिखने की जिम्मेदारी भगत सिंह छात्र एकता मंच ने ली है। डीयू प्रशासन ने मॉरिस नगर थाने में शिकायत की है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालकर देखकर सुबूत एकत्र कर रही है।

डीयू के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की दीवारों पर नारे लिखे गए हैं। इनमें चुनाव बहिष्कार करो, नक्सलबाड़ी जिंदाबाद जैसे नारे लिखे गए हैं। नारों के पीछे भगत सिंह छात्र एकता मंच का नाम लिखा गया है। मंच ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली है। मंच की पदाधिकारी और दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की छात्रा बादल ने कहा, ₹देश में आम जनता की आवाज नहीं सुनी जा रही है। संसद में सिर्फ एक खास वर्ग की बात की जा रही है। अब देश को जनवादी क्रांति की जरूरत है। हमनें नारे लिखकर लोगों से क्रांति से जुड़ने का आह्वान किया है।

ABVP ने नारे लिखे जाने की निंदा की

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नारे लिखे जाने की निंदा की है। मॉरिस नगर थाने में शिकायत कर इस घटना में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई और नारे तत्काल मिटाने की मांग की है। एबीवीपी ने एक बयान में कहा है कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब दिल्ली का युवा मतदाता लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेने के लिए उत्साहित है, तो इस तरह के अलोकतांत्रिक नारे लिखे गए।

नारे मिटाए जा रहे: प्रो. रजनी अब्बी

एबीवीपी इसका कड़ा विरोध कर कार्रवाई की मांग करती है कि इस पूरे रोड पर लगे सीसीटीवी फुटेज को जांचकर कार्रवाई की जानी चाहिए। डीयू की प्रॉक्टर प्रो. रजनी अब्बी ने कहा है कि नारे मिटाए जा रहे हैं। मारिस नगर थाने में हमारी ओर से शिकायत दी गई है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। पुलिस को सहयोग किया जा रहा है।

केजरीवाल की गिरफ्तारी और मालीवाल से मारपीट का मामला गर्माया, शोर में दब गए दिल्ली के मुद्दे

दिल्ली में बीते दो माह से अधिक समय तक लोकसभा चुनाव का प्रचार चला। प्रचार के शुरू में प्रदूषण यमुना की सफाई पेयजल जाम मुक्त दिल्ली आसान कनेक्टिविटी शिक्षा स्वास्थ्य कोराबार जैसे दिल्ली से संबंधित मुद्दे उठे लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उसके बाद आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास में मारपीट का मामला उछलने से पीछे रह गए।

नई दिल्ली। प्रचार का शोर थम गया है। 16 मार्च को चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव प्रचार शुरू हो गया था, लेकिन इसमें तेजी 29 अप्रैल को छठे चरण के मतदान की अधिसूचना जारी होने के साथ आई। चुनावी समर में जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी पार्टियों ने ताकत झोंकी।

भाजपा तीसरी बार सभी सातों सीटें जीतने के संकल्प के साथ और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन उसके विजय अभियान को रोकने के लिए बड़े नेताओं को मैदान में उतारा। नुक्कड़ बैठकों, छोटे-बड़े चुनावी जनसभाओं, डिजिटल वैन सहित अन्य माध्यमों से अपनी बात मतदाताओं तक पहुंचाने का प्रयास हुआ।

दो माह से अधिक समय तक चले चुनाव प्रचार के शुरू में प्रदूषण, यमुना की सफाई, पेयजल, जाम मुक्त दिल्ली, आसान कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कोराबार जैसे दिल्ली से संबंधित मुद्दे उठे लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उसके बाद आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास में मारपीट का मामला उछलने से पीछे रह गए। प्रचार के अंतिम चरण में भाजपा व आप दोनों इसी विषय पर एक दूसरे को घेरते नजर आए। चुनाव प्रचार में आप व कांग्रेस गठबंधन की तुलना में भाजपा आगे रही।

बड़े नेताओं ने किया भाजपा प्रत्याशियों का प्रचार

भाजपा ने दो मार्च और उसके कुछ दिनों बाद दो अन्य प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। इनके नाम घोषित होने के पहले ही पार्टी ने सभी संसदीय क्षेत्रों में चुनाव प्रबंधन का काम शुरू कर दिया था।

गाजियाबाद की सड़कों को मिलेगा यूनिक आईडी नंबर, संपत्तियों का डाटा होगा ऑनलाइन; होंगे ये फायदे

गाजियाबाद जिले की सड़कों और नालों की पहचान के लिए प्रत्येक को यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा। एक माह में यह कार्य पूरा हो जाएगा इसके बाद विकास कार्यों में किए जा रहे फर्जीवाड़े पर अंकुश लग सकेगा तो दूसरी तरफ नागरिकों को पता चल सकेगा कि उनसे कितनी दूरी पर शौचालय पेट्रोल पंप मार्केट सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद। नगर निगम क्षेत्र में स्थित भवनों से लेकर सड़कों, नालों, स्ट्रीट लाइटों, शौचालयों सहित अन्य संपत्तियों का डाटा जल्द ही एक क्लिक पर नगर निगम के अधिकारियों के पास उपलब्ध होगा। इसके लिए सर्वे कराकर भौगोलिक सूचना प्रणाली की मैपिंग का कार्य कराया जा रहा है।

सड़कों और नालों की पहचान के लिए प्रत्येक को यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा। एक माह में यह कार्य पूरा हो जाएगा, इसके बाद विकास कार्यों में किए जा रहे फर्जीवाड़े पर अंकुश लग सकेगा तो दूसरी तरफ नागरिकों को पता चल सकेगा कि उनसे कितनी दूरी पर शौचालय, पेट्रोल पंप, मार्केट सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।

स्ट्रीट लाइटें लगाने सहित अन्य कार्य कराए गए

नगर निगम सीमा के क्षेत्र में नगर निगम के साथ ही आवास विकास परिषद, जीडीए, एनएचएआई, लोक निर्माण विभाग द्वारा भी नागरिकों को सुविधाएं देने के लिए सड़कें बनाने, शौचालय बनाने, नालों, नालियों का निर्माण कार्य, स्ट्रीट लाइटें लगाने सहित अन्य कार्य कराए गए हैं। अब तक नगर निगम के पास इसकी डिजिटल जानकारी उपलब्ध नहीं थी, जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को पत्र भेजकर जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। इसमें देरी लगती है, विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं।

कई बार बनी हुई सड़कों की मरम्मत के लिए प्रस्ताव बना दिया जाता है, अधिकारियों के संज्ञान में मामला न होने के कारण बजट जारी हो जाता है। लेकिन अब ऐसा न हो, इसके लिए सर्वे में सड़कों, नालों, स्ट्रीट लाइटों, शौचालयों सहित सरकारी जमीनों की भी जानकारी जुटाई गई है, जिसे पोर्टल के साथ ही नगर निगम द्वारा संचालित गाजियाबाद 311 एप पर फीड किया जाएगा।

अन्य सुविधाओं के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी

इसके बाद नगर निगम के अधिकारियों को यह पता चल सकेगा कि नगर निगम सीमा क्षेत्र में कुल कितने कितने किलोमीटर सड़कें बनी हैं, कहां पर मरम्मत की आवश्यकता है। दूसरे विभाग की कितनी सड़कें है। कितने स्ट्रीट लाइट लगी हैं और इनमें से कितनी चालू और कितनी बंद हैं। सरकारी जमीनों, नालों, नालियों, शौचालयों सहित अन्य सुविधाओं के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी।

बृहस्पतिवार को नगर निगम कार्यालय

में इस संबंध में नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक की अध्यक्षता में बैठक की गई। जिसमें रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर लखनऊ से आए विज्ञानी आलोक सैनी द्वारा प्रजेंटेशन दिया गया।

संपत्तियों की जानकारी 70 श्रेणी में तैयार की गई

उन्होंने बताया कि सर्वे के दौरान नगर निगम की संपत्तियों के बारे में जो जानकारी एकत्र की गई है, उसकी किस तरह से डिजिटल डायरी तैयार की जा रही है। जिससे कि अधिकारियों को आसानी से नगर निगम की प्रत्येक संपत्ति के बारे में जानकारी हो सकेगी। नगर निगम की संपत्तियों की जानकारी 70 श्रेणी में तैयार की गई है, जिसे एप और पोर्टल पर अपडेट करने का कार्य किया जा रहा है।

सर्वे के माध्यम से सड़कों की लंबाई, चौड़ाई, स्थिति के बारे में पता चल सकेगा। किस सरकारी जमीन पर कब्जा है और कितनी कब्जामुक्त है, यह भी पता चल सकेगा। प्रत्येक छह माह में इस तरह का सर्वे कराकर डाटा अपडेट किया जाएगा। - विक्रमादित्य सिंह मलिक, नगर आयुक्त

नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बिजली बिलों की गड़बड़ी से मिलेगा छुटकारा, लगेंगे पांच लाख प्रीपेड मीटर

गौतमबुद्ध नगर में पहले चरण में ग्रेटर नोएडा व जेवर में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। दोनों ही क्षेत्रों सर्वे और ट्रायल का काम पूरा हो चुका है। 4जी स्मार्ट मीटर लगने के बाद मीटरिंग की व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगी। मीटर सिम से चलेगा। इससे उपभोक्ता का मोबाइल भी कनेक्ट रहेगा। साथ ही यह विद्युत निगम के कंट्रोल रूम से भी जुड़ा रहेगा।

नोएडा। गौतमबुद्ध नगर समेत पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के 14 जिलों में 4जी स्मार्ट मीटर लगाने की तैयार अंतिम चरण में पहुंच गई है। जिले में पहले चरण में ग्रेटर नोएडा व जेवर में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। दोनों ही क्षेत्रों सर्वे और ट्रायल का काम पूरा हो चुका है।

अचार संहिता खत्म होत हुए। मीटर लगाने का काम शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत मार्च 2025 तक गौतमबुद्ध नगर में इलेक्ट्रानिक को पूरी तरह 4जी स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बदला जाना है। कुल पांच लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।

मोबाइल पर देख सकेंगे मीटर रीडिंग

अभी कुछ जगह बहुमंजिला सोसायटियों में प्रीपेड मीटर लगे हैं, लेकिन ये स्मार्ट नहीं है। लोग एडवांस में रिचार्ज तो करते है, लेकिन अभी मीटर रीडिंग आदि की जानकारी मोबाइल पर नहीं देख पाते हैं। 4जी स्मार्ट मीटर लगने के बाद मीटरिंग की व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगी। मीटर सिम से चलेगा।

इससे उपभोक्ता का मोबाइल भी कनेक्ट रहेगा। साथ ही यह विद्युत निगम के कंट्रोल रूम से भी जुड़ा रहेगा। उपभोक्ता को मोबाइल की तरह अपना मीटर रिचार्ज कराना पड़ेगा। बिजली रिचार्ज के अलावा उपभोक्ता अपनी प्रत्येक दिन खपत भी देख सकेंगे। बिजली की स्थिति देख सकेंगे।

इससे उपभोक्ता और विद्युत निगम दोनों तरफ से निगरानी पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगी। मीटर रीडिंग की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। घर और दुकान की बिजली खपत का अलग-अलग आडिट हो सकेगा। शार्ट सर्किट होने की स्थिति में अपने आप बिजली कट जाएगी।

पहले की तरह मिलता रहेगा बिल

विद्युत निगम के अधिकारियों ने बताया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बाद भी मासिक बिल बनते रहेंगे। इस व्यवस्था में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। उपभोक्ता बिल भी भुगतान कर सकता है और अपने आप रिचार्ज भी कर सकता है।

बस तय समय पर रिचार्ज नहीं होने पर अपने सिस्टम से ही बिजली कट जाएगी। इसके लिए खंभे से केबल काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि, भविष्य में प्रीपेड व्यवस्था ही लागू हो जाएगी। इसके बाद बिजली बकाया जैसी समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी।

भाजपा पार्षद की गिरफ्तारी का पार्षदों ने जताया विरोध, हापुड़ रोड जाम, पुलिस से धक्का-मुक्की

आरोपित पार्षद ने अतिक्रमण का विरोध जताया था इस दौरान दंपती से विवाद हुआ और मारपीट हुई लेकिन पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई की। पार्षदों की पुलिस से धक्का-मुक्की और नोकझोंक भी हुई। पार्षद शीतल देओल ने बताया कि डीआइजी ने बृहस्पतिवार तक का समय मांगा है यदि बृहस्पतिवार दोपहर तक निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई तो महापौर से मुलाकात कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।

गाजियाबाद। मोहन नगर में रविवार रात दो बजे दुकानदार दंपती से मारपीट के मामले में गिरफ्तार किए गए भाजपा पार्षद सुधीर की गिरफ्तारी के विरोध में 50 से अधिक पार्षद उतर आए हैं।

बुधवार सुबह पहले पहले उन्होंने महापौर से उनके आवास पर दोपहर में कार्यालय जाकर मुलाकात की और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। इसके बाद देर शाम को पुलिस कमिश्नर से मिलने उनके आवास पर जाने लगे, इंग्राहम कट के पास पुलिस ने बेरिकेडिंग कर पार्षदों को रोकना चाहा तो पार्षदों ने विरोध जताया।

पार्षदों की पुलिस से धक्का- मुक्की और नोकझोंक भी हुई। इस दौरान हापुड़ रोड पर जाम लग गया। डीआइजी कल्पना सक्सेना के समझाने पर पार्षद हापुड़ रोड से हटे और उनसे बातचीत करने के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में गए, तब हापुड़ रोड पर यातायात सुचारू हो सका।

मारपीट के मामले में की गई कार्रवाई

सुबह महापौर के आवास पर पहुंचकर पार्षदों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि मारपीट के मामले में पुलिस ने लूट सहित अन्य संगीन धाराओं में कार्रवाई की है। आरोपित पार्षद ने अतिक्रमण का विरोध जताया था, इस दौरान दंपती से विवाद हुआ और मारपीट हुई लेकिन पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई की।

महापौर से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। पार्षदों की मौजूदगी में ही महापौर सुनीता दयाल ने एसीपी नंदग्राम रवि कुमार को आवास पर बुलाया। उनसे कहा कि इस तरह से जनप्रतिनिधि की गिरफ्तारी गलत है, पहले मामले की निष्पक्ष जांच की जाती, इसके बाद जो दोषी होता उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती।

पार्षदों ने इस मामले में एसएचओ साहिबाबाद और मोहन नगर चौकी प्रभारी को निलंबित करने की मांग की है। मांगे न मानी जाने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है।

एसीपी नंदग्राम रवि कुमार सिंह ने कहा कि महापौर और पार्षदों ने बातचीत के दौरान जो मांगें

की हैं, उनसे उच्चाधिकारियों से अवगत कराएंगे। लेकिन देर शाम तक मांगे नहीं माने जाने पर पार्षद शीतल देओल, पूनम सिंह, धीरेंद्र, अजय शर्मा सहित 50 से अधिक पार्षद कलक्ट्रेट के सामने पहुंचे।

हापुड़ रोड पर लगाया जाम

उन्होंने हापुड़ रोड पर जाम लगा दिया। इससे हापुड़ रोड पर लगभग एक किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सूचना पर डीआइजी कल्पना सक्सेना, डीसीपी सिटी ज्ञानन्जय सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे।

पार्षदों को हटाने की कोशिश की तो धक्का - मुक्की और नोकझोंक हुई। डीआइजी कल्पना सक्सेना ने पार्षदों को समझाया और वार्ता के लिए अपने साथ अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में लेकर गईं, जहां पर उन्होंने पार्षदों का पक्ष सुना।

पार्षदों ने साहिबाबाद थाने के एसएचओ और मोहननगर चौकी के प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। डीआइजी ने निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि इस मामले में जांच कराई जाएगी, यदि एसएचओ और चौकी प्रभारी की लापरवाही मिली तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पार्षद शीतल देओल ने बताया कि डीआइजी ने बृहस्पतिवार तक का समय मांगा है, यदि बृहस्पतिवार दोपहर तक निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई तो महापौर से मुलाकात कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।

पार्षद की पत्नी ने भी दी तहरीर

इस मामले में भाजपा पार्षद की पत्नी स्वाति ने बुधवार को पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने बताया कि पति सुधीर कुमार बहन की रिंग सेरेमनी से घर लौट रहे थे, इस दौरान फोन पर उनको मोहन नगर में माल के पास झगड़े की सूचना मिली।

वह पहुंचे तो देखा दो पक्षों में झगड़ा चल रहा था, वह झगड़ा शांत कराने लगे तो उनसे गाली गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई, झगड़ा बढ़ा तो सुधीर वहां से चले गए। मामले की जानकारी होने पर स्वाति व उनके परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो उनसे भी गाली गलौज की गई और धमकी दी गई।

कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस के हिन्दू विरोध की उग्रता

ललित गर्ग

पश्चिम बंगाल ही नहीं, अन्य गैर-भाजपा सरकारों के प्रांतों में हिन्दुओं को प्रताड़ति करने के घटनाक्रम सामने आते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो हिन्दुओं के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उग्र और हिंसक प्रदर्शन होता रहा हैं।

लोकसभा चुनाव के दो चरण शेष रहे हैं, चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी राजनीतिक दल अपनी बढ़त बनाने के लिये कुछ अतिश्योक्तिपूर्ण करने का प्रयास करते हुए राष्ट्र की एकता-अखण्डता एवं बहुसंख्यक हिन्दू धर्म विरोधी स्वरों को बुलंद किये हुए है और अपनी मर्यादाओं को भूल रहे हैं। विशेषतः इंडिया गठबंधन से जुड़े दल एवं बाहर से समर्थन देने की बात करने वाले दल ऐसा दूषित प्रचार कर रहे हैं, जिससे न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है बल्कि ऐसे दलों को राजनीतिक लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावनाएं प्रबल हो रही है। इन चुनावों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस एवं इंडिया गठबंधन के अन्य दल हिन्दुओं से, हिन्दू मन्दिरों-भगवानों-संतों एवं हिन्दू पर्वों से नफरत का बिगुल हर मोड़ पर बजाते रहे हैं जो हर रोज सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए हिन्दू संतों को राजनीति में घसीटने की कोशिश की है। उन्होंने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ से जुड़े संतों पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये लोग भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिये ओबीसी आरक्षण पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय पर कानून की धज्जियां उडाते हुए उंगली उठाई है। इस प्रकार कानून की अवमानना वह नेता ही खड़ी कर सकता है, जिसे एक खास वर्ग के वोट चाहिए। संतों को लेकर राजनीतिक टिप्पणी करना, निःसंदेह आपत्तिजनक है एवं दुर्भाग्यपूर्ण है।

कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस हिन्दुओं को अपने ही देश में सेकेंड क्लास सिटिज़न एवं अल्पसंख्यक बनाना चाहती है। मुस्लिम तुष्टीकरण की इन दलों की सोच एवं नीति न केवल उनके घोषणा-पत्रों में बल्कि उनके बयानों में स्पष्ट झलक रही है। सभी विपक्षी दलों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है, राजनीतिक दलों का एकतरफा रवैया हमेशा से समाज को दो वर्गों में बांटता रहा है एवं सामाजिक असंतुलन तथा रोष का कारण रहा है। बदले हुए राजनीतिक हालात इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किसी भी एक वर्ग की अनदेखी कर कोई भी दल राजसत्ता का आनंद नहीं उठा सकता। लेकिन लगातार जीत की ओर बढ़ रहे भाजपा को हराने के लिये इन दलों को मुस्लिम वोटों का ही सहारा नजर आ रहा है, जिसके चलते ये हिन्दू विरोध को प्रचंड किये हुए।

ममता बनर्जी ने अपने शासन में मुस्लिमों को खुश करने एवं उनके वोटों को अपने पक्ष में करने के लिये हिन्दू विरोध का कोई मौका नहीं छोड़ा है। ममता ने रामकृष्ण मठ, मिशन और भारत सेवाश्रम संघ पर झूठा एवं भ्रामक आरोप लगाया है कि ये हिन्दू संगठन भाजपा के पक्ष में काम कर रहे हैं, जबकि इन संगठनों की ओर से एक बार भी भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान नहीं किया गया है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में इस्लामिक संगठनों एवं चर्चों के द्वारा भाजपा के विरोध में किसी एक विशेष दल के पक्ष में मतदान करने के प्रकरण बार-बार सामने आये हैं। चुनावों को धार्मिक एवं साम्प्रदायिक रंग देने की इन विडम्बनापूर्ण स्थितियों पर आज तक ममता बनर्जी ने एक भी बयान नहीं दिया है। इसलिए भी कहा जा सकता हैं कि बिना किसी प्रमाण हिन्दू संतों पर निशाना साधने का अभिप्राय यही है कि ममता बनर्जी की निगाहें कहीं और है निशाना कहीं और है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा ममता बनर्जी पर संतों को धमकाने का आरोप निराधार नहीं है। क्योंकि एक संत कार्तिक महाराज ने मुख्यमंत्री ममता को कानूनी नोटिस भेज कर कहा है कि ममता बनर्जी के बयान निराधार, झूठे और अपमानजनक है।

पश्चिम बंगाल ही नहीं, अन्य गैर-भाजपा सरकारों के प्रांतों में हिन्दुओं को प्रताड़ति करने के घटनाक्रम सामने आते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो हिन्दुओं के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उग्र और हिंसक प्रदर्शन होता रहा हैं। पिछले कुछ सालों से हमेशा यह देखा गया है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता सत्ता पाकर भाजपा समर्थकों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। वर्ष 2021 में भी तृणमूल कांग्रेस के जीतने के बाद राज्य में बवाल हुआ था और पंचायत चुनाव जीतने के बाद भी उसके कार्यकर्ताओं ने हिंसक उत्पात मचाया था। उस समय भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों को खोज-खोजकर हमले हुए थे। ऐसे स्थिति में और ऐसे कार्यकर्ताओं के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हिन्दू संगठनों एवं धर्मगुरुओं के भाजपा के पक्ष में होने का बयान संतों के लिए जान तक का खतरा पैदा कर सकता है। ऐसा हुआ भी है, ममता बनर्जी के बयान के बाद कुछ हमलावर जलपाईगुड़ी स्थित रामकृष्ण मिशन के आश्रम में घुस गए। उन्होंने भिक्षुओं पर हमला किया, सीसीटीवी आदि तोड़े दिए। याद हो कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में पहली बार संतों पर दोष लगाकर उनके खिलाफ माहौल बनाने का काम नहीं हुआ।

मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने के लिये इंडिया गठबंधन के दल विशेषतः कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यकों को भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अल्पसंख्यकों में सिख, पारसी, यहूदी, जैनी, बौद्ध आदि धर्म आते हैं, लेकिन कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम परस्ती करते आई है। ओबीसी आरक्षण पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने जिस तरह से कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय पर उंगली उठाई है, उससे तो यही लगता है कि राजनीतिक वोट बैंक के लिए संविधान की जितनी अवमानना की जा सकती है, वह की जाती रहेगी। सामनेवाले को घेरने के लिए उसी संविधान की आड़ भी ली जाएगी। ममता ने मुस्लिमों को ओबीसी सर्टिफिकेट देकर उन्हें तरह-तरह से लाभ पहुंचाने का षड़यंत्र किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चुनावी रैलियों में इंडी गठबंधन के सत्ता में आते ही एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को मुस्लिमों को देने की बात कह रहे हैं, वह भी इस घटना से साफ होता नजर आ रहा है। धर्म के आधार पर आरक्षण भारतीय संविधान में निहित मूल्यों और सिद्धांतों के खिलाफ है।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 मई को पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का आदेश दिया है। जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती और राजशेखर की बेंच ने कहा कि 2011 से प्रशासन ने किसी नियम का पालन किए बगैर ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर दिए। इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक है। यह सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सलाह माने बगैर जारी किए गए। इसलिए इन सभी सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी या मिलने वाली है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी।

ममता बनर्जी सरकार से पहले वामपंथी शासन काल में भी हिन्दू संतों को माकपा की सरकार ने निशाना बनाया था। तब परिणाम यह हुआ था कि कोलकाता में सरेआम 16 भिक्षु और 1 साध्वी हत्या की गई थी। आज उस नरसंहार को 'बिजोन सेतु नरसंहार' कहा जाता है। राजनीतिक बेशर्मी देखिए कि सरेआम संतों की हत्याएं की गईं लेकिन आज तक उस नरसंहार में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। माकपा सरकार पर आरोप हैं कि उसने इस मामले से संबंधित तथ्यों को छिपाया। नरसंहार की जाँच के लिए बने आयोगों को न तो माकपा सरकार ने सहयोग दिया और न ही तृणमूल कांग्रेस ने। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान के बाद से भय का वातावरण बन गया है। आश्रमों एवं संतों को नुकसान पहुँचाने की आशंका गहरा गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सांप्रदायिक बयान की जितनी निंदा की जाए कम है। यह तो निश्चित है कि वर्तमान कांग्रेस, पूर्व में आजादी से अब तक की कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ही की है। इस सोच के कारण कांग्रेस एवं अन्य इंडिया गठबंधन के दलों ने राम मंदिर उद्घाटन से भी दूरी बनाये रखी। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस की हिंदू विरोधी छवि का नुकसान इन दलों को निश्चित रूप से मिलेगा। क्या वास्तव में ये दल अपनी बिगड़ती छवि एवं नुकसान से परेशान है? या इस बात से कि उसकी छवि बिगाड़कर 'हिंदू विरोधी' बताने की कोशिश की जा रही हैं? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि वे अपनी बदहाली के कारणों को समझना भी चाहते है या नहीं?

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 मई को पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का आदेश दिया है। जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती और राजशेखर की बेंच ने कहा कि 2011 से प्रशासन ने किसी नियम का पालन किए बगैर ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर दिए। इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक है। यह सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सलाह माने बगैर जारी किए गए। इसलिए इन सभी सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी या मिलने वाली है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी।

स्कोडा इंडिया अगले साल लॉन्च करेगा ये 5 नई कारें! जानिए पूरी डिटेल

परिवहन विशेष न्यूज

Skoda Auto India अगले 12 से 18 महीनों में घरेलू बाजार के अंदर 6 नए पैसेंजर व्हीकल पेश करने की योजना बना रही है। सब-फोर-मीटर सेगमेंट को अपनाते हुए यह कॉम्पैक्ट एसयूवी अपने समकक्षों कुशाक और स्लाविया के साथ MQB A0 IN प्लेटफॉर्म साझा करेगी। New-Gen Skoda Kodiaq को लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है।

नई दिल्ली। Skoda Auto India अगले 12 से 18 महीनों में घरेलू बाजार के अंदर 6 नए पैसेंजर व्हीकल पेश करने की योजना बना रही है। इसमें प्रमुख आकर्षण एक कॉम्पैक्ट एसयूवी होगी, जिसे पूरी तरह से लोकली डेवलप किया जाएगा। आइए, इनके बारे में जान लेते हैं।

Skoda Compact SUV

सब-फोर-मीटर सेगमेंट को अपनाते हुए यह कॉम्पैक्ट एसयूवी अपने समकक्षों, कुशाक और स्लाविया के साथ MQB A0 IN प्लेटफॉर्म साझा करेगी। इसके हुड के नीचे 1.0 लीटर थ्री-पॉट टर्बो पेट्रोल इंजन का उपयोग किया जाएगा, जो 115 PS अधिकतम पावर और 175 Nm का उत्पादन करेगा और यह मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ उपलब्ध होगा।

Skoda Kushaq और Slavia Facelift

अगले साल फेसलिफ्टेड स्कोडा कुशाक और स्लाविया के आने का काफी इंतजार है। इन नए मॉडलों में लेवल 2 एडास तकनीक और 360-डिग्री कैमरा सिस्टम सहित अन्य नई तकनीकें शामिल होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, बाहरी और आंतरिक दोनों को अपडेट के लिए स्लेट किया गया है, जिसका उद्देश्य इन मॉडलों की वर्तमान पीढ़ी की अपील को लंबे समय तक बनाए रखना है।

New-Gen Skoda Kodiaq

New-Gen Skoda Kodiaq को लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। खबर है कि नई पीढ़ी की कोडियाक अगले 12 महीनों के अंदर इंडियन मार्केट में एंट्री करेगी। MQB Evo प्लेटफॉर्म पर निर्मित ये एसयूवी कॉस्मेटिक बदलाव और इंटीरियर अपडेट के साथ आई है। इसे 2.0L टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाना जारी रखा जाएगा।

New Skoda Superb और Octavia

New Skoda Superb के भी लॉन्च की उम्मीद है, लेकिन इसका पूर्ववर्ती मॉडल कुछ महीने पहले CBU रूट के माध्यम से भारत लौटा है। हालांकि, ऑक्टाविया की सटीक लॉन्च टाइमलाइन अभी भी अज्ञात है, लेकिन उद्योग की उम्मीदें 2025 में शुरू होने की ओर इशारा करती हैं।

किआ सेल्टॉस के कर्टेन एयरबैग्स में आई दिक्कत, कंपनी को वापस बुलानी पड़ीं 292 गाड़ियां; अब फ्री में बनाकर देंगे

परिवहन विशेष न्यूज

Kia ने कर्टेन एयरबैग में समस्या के कारण Seltos SUV के 292 यूनिट वापस मंगाए हैं। Kia ने एक बयान में कहा कि सेल्टोस की प्रभावित इकाइयों पर साइड कर्टेन एयरबैग दुर्घटना के बिना ही खुल सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई स्पेक सेल्टोस 2.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है जो 148 बीएचपी और 180 एनएम पीक टॉर्क के लिए ट्यून किया गया है।

नई दिल्ली। Kia Australia ने कर्टेन एयरबैग में समस्या के कारण Seltos SUV के 292 यूनिट वापस मंगाए हैं। रिकॉल से प्रभावित किआ सेल्टोस का निर्माण 2023 में किया गया था और ये फेसलिफ्टेड मॉडल हैं। आइए, पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।

कर्टेन एयरबैग में आई दिक्कत

Kia ने एक बयान में कहा कि सेल्टोस की प्रभावित इकाइयों पर साइड कर्टेन एयरबैग दुर्घटना के बिना ही खुल सकते हैं। इस समस्या को एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जो चालक का ध्यान भटका सकता है। इसके अलावा चोट लगने और बड़े सड़क दुर्घटना का भी खतरा है।

कंपनी ने क्या कहा?

किआ ऑस्ट्रेलिया ने अपने रिकॉल नोटिस में लिखा है, ₹एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण, साइड कर्टेन एयरबैग बिना किसी चेतावनी के खुल सकते हैं। एयरबैग के अनजाने में खुल जाने से चालक का ध्यान भटक सकता है और वाहन में बैठे लोगों के घायल होने या मौत का जोखिम बढ़ सकता है।

फ्री में होगी मरम्मत

किआ ने कहा कि प्रभावित वाहनों के मालिकों को तुरंत अपने पसंदीदा किआ डीलरशिप से संपर्क करना चाहिए और कर्टेन एयरबैग की जांच और उसे मुफ्त में बदलने के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना चाहिए।

Kia Seltos का इंजन और स्पेसिफिकेशन

ऑस्ट्रेलियाई स्पेक सेल्टोस 2.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है, जो 148 बीएचपी और 180 एनएम पीक टॉर्क के लिए ट्यून किया गया है। 1.6-लीटर टर्बो पेट्रोल मोटर भी है जो 196 बीएचपी और 265 एनएम का उत्पादन करता है।

2.0-लीटर मोटर को CVT ऑटोमैटिक यूनिट के साथ जोड़ा गया है, जबकि टर्बो पेट्रोल को 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। ऑस्ट्रेलिया के लिए किआ सेल्टोस को ऑटोमेकर के दक्षिण कोरियाई प्लांट से निर्यात किया जाता है।

पोर्से की पहली इलेक्ट्रिक कार कैसे बनी गेम चेंजर? पढ़िए Taycan की कहानी

Taycan एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्सकार है। भारतीय बाजार में कंपनी इसे कुल 5 वेरिएंट में सेल करती है। Taycan RWD और Taycan 4S में 79.2 kWh का बैटरी पैक है जबकि Taycan GTS Taycan Turbo और Taycan Turbo S में 93.4 kWh का बैटरी पैक है। Taycan एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्सकार है। भारतीय बाजार में कंपनी इसे कुल 5 वेरिएंट में सेल करती है।

नई दिल्ली। पुणे में हुए Porsche Taycan Accident की खूब चर्चा हुई है। टायकन दुनियाभर की फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक कारों में से एक है। इंडिया में ये कार चुनिंदा लोगों के पास ही है, जिसमें पुणे की सुपरकार भी शामिल है। आइए, Taycan के बारे विस्तार से जान लेते हैं।

Porsche की पहली Electric Car

टायकन ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दुनिया में पोर्श के प्रवेश को चिह्नित किया है। कंपनी की ये इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्सकार Tesla Model S और Mercedes EQS AMG जैसी अन्य कारों को टक्कर देती है। 2019 में वैश्विक बाजारों में अपने शुरुआती लॉन्च के बाद से टायकन ने मजबूत प्रदर्शन किया है।

Taycan की इंडियन जर्नी

Taycan एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्सकार है। भारतीय बाजार में कंपनी इसे कुल 5 वेरिएंट में सेल करती है। Taycan RWD और Taycan 4S में 79.2 kWh का बैटरी पैक है, जबकि Taycan GTS, Taycan Turbo और Taycan Turbo S में 93.4 kWh का बैटरी पैक है।

Porsche Taycan की रेंज एक बार चार्ज करने पर लगभग 390 किलोमीटर है। भारतीय बाजार में ये CBU रूट से आती है और टैक्स लगने से पहले इसकी कीमत 1.61 करोड़ रुपये से 2.44 करोड़ रुपये के बीच है।

बैटरी, मोटर और परफॉरमेंस

Taycan एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्सकार है। भारतीय बाजार में कंपनी इसे कुल 5 वेरिएंट में सेल करती है। Taycan RWD और Taycan 4S में 79.2 kWh का बैटरी पैक है, जबकि Taycan GTS, Taycan Turbo और Taycan Turbo S में 93.4 kWh का बैटरी पैक है। Porsche Taycan की रेंज एक बार चार्ज करने पर लगभग 390 किलोमीटर है। Porsche Taycan का पावरट्रेन 750 bhp तक की शक्ति और 1050 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है। ये 3 सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है।

Flex-Fuel व्हीकल कैसे करते हैं काम? जानिए इनके नफा-नुकसान

Flex-Fuel Vehicles 100 प्रतिशत पेट्रोल या 100 प्रतिशत बायो-इथेनॉल और उनके मिश्रणों के संयोजन पर चलने में सक्षम होते हैं। ये इंजन फ्यूल पंप और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को एडजस्ट करने के लिए इथेनॉल-कॉम्पेटिवल कंपोनेंट्स का उपयोग करते हैं। फ्लेक्स-फ्यूल इंजन फ्यूल मिक्स सेंसर और इंजन कंट्रोल मॉड्यूल (ECM) प्रोग्रामिंग से लैस होते हैं। ये मिश्रित ईंधन के किसी भी अनुपात को समायोजित कर सकते हैं।

नई दिल्ली। फ्लेक्सी-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FFV-SHEV) भविष्य में बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari ने पिछले साल अक्टूबर में फ्लेक्स-फ्यूल इंजन वाली भारत की पहली कार पेश की थी। आइए जान लेते हैं कि इस तरह के इंजन किस तरह काम करते हैं और इनके क्या फायदे हैं?

फ्लेक्स फ्यूल क्या होते हैं?

फ्लेक्स फ्यूल वाहन 100 प्रतिशत पेट्रोल या 100 प्रतिशत बायो-इथेनॉल और उनके मिश्रणों के संयोजन पर चलने में सक्षम होते हैं। ये मूल रूप से एक फ्लेक्सिबल फ्यूल होता है, जो वाहन के आंतरिक दहन इंजन (ICE) के साथ संगत है। यह पेट्रोल या डीजल के साथ-साथ ईंधन के मिश्रण पर भी चलता है। एमीशन की बात करें, तो नॉर्मल पेट्रोल और डीजल इंजन के मुकाबले ये कम पॉल्यूशन करते हैं।

कैसे काम करते हैं फ्लेक्स फ्यूल इंजन?

फ्लेक्स-फ्यूल इंजन फ्यूल मिक्स सेंसर और इंजन कंट्रोल मॉड्यूल (ECM) प्रोग्रामिंग से लैस होते हैं। ये मिश्रित ईंधन के किसी भी अनुपात को समायोजित कर सकते हैं। ये इंजन फ्यूल पंप और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को एडजस्ट करने के लिए इथेनॉल-कॉम्पेटिवल कंपोनेंट्स का उपयोग करते हैं।

देश की पहली फ्लेक्स-फ्यूल इंजन वाली कार

टोयोटा मोटर ने कोरोला एल्टिस में पायलट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में फ्लेक्स-फ्यूल इंजन लगाया था। केंद्र द्वारा गन्ने से प्राप्त ईंधन के मिश्रण को मंजूरी दिए जाने के बाद यह भारतीय सड़कों पर इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल पर चलने वाली पहली कार थी। आपको बता दें कि फ्लेक्स-फ्यूल इंजन पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, यूरोपीय संघ और चीन जैसे देशों में काफी पॉपुलर हैं।

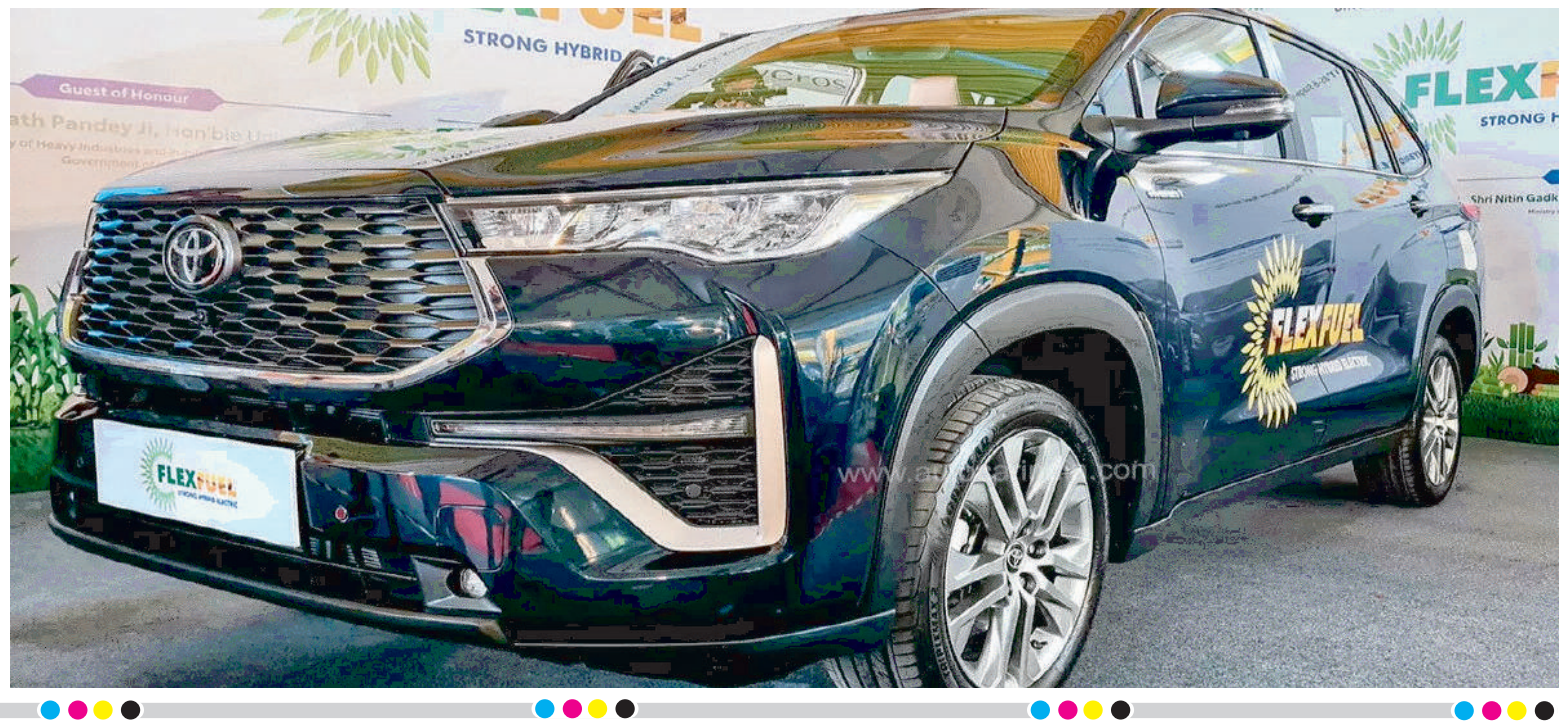

महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से लें प्रेरणा

अनुज आचार्य

इतिहासकारों के अनुसार बुद्ध के जीवनकाल को 563-483 ई. पू. के मध्य माना गया है। अधिकांश लोग नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान को बुद्ध का जन्म स्थान मानते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में हुई थी।

यही वजह भी है कि इनकी शिक्षाओं को विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण के दृष्टिगत स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित किया गया है। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ है जागा हुआ, एनलाइटेन्ड अर्थात जिसे सत्य और आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो। यहां इसका तुच्छ अर्थ केवल राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ से नहीं है, बल्कि उनके पहले भी अनेक समाधिस्थ व्यक्तियों को चैतन्यता, सत्य और जीवन के रहस्यों से साक्षात्कार होने के कारण बुद्ध की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार देखें तो अपने को जानने की यह तपस्या और क्रिया बाद में भी तथा भविष्य में भी निरंतर चलती रहेगी'

भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आज भारतवर्ष में बुद्ध पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है। इतिहासकारों के अनुसार बुद्ध के जीवनकाल को 563-483 ई. पू. के मध्य माना गया है। अधिकांश लोग नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान को बुद्ध का जन्म स्थान मानते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में हुई थी। बुद्ध पूर्णिमा का संबंध बुद्ध के जन्म से ही नहीं है, बल्कि इसी पूर्णिमा तिथि को वर्षों वनों में भटकने व कठोर तपस्या करने के पश्चात बोधगया में बोधिवृक्ष नीचे बुद्ध को सत्य का ज्ञान हुआ था। इसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरी दुनिया में एक नई रोशनी पैदा की और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ भी था। इस प्रकार देखें तो उनका जन्म, सत्य तथा ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण एक ही दिन यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। आज भौतिकतावाद और जीवन की आपाधापी के बीच बौद्ध जीवन मार्ग और महात्मा बुद्ध के संदेशों का महत्व और बढ़ गया है। बुद्ध की शिक्षाएं प्रत्येक काल एवं परिस्थितियों में मानवमात्र का मार्गदर्शन करती आई हैं।

यही वजह भी है कि इनकी शिक्षाओं को विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण के दृष्टिगत स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित किया गया है। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ है जागा हुआ, एनलाइटेन्ड अर्थात जिसे सत्य और आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो। यहां इसका तुच्छ अर्थ केवल राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ से नहीं है, बल्कि उनके पहले भी अनेक समाधिस्थ व्यक्तियों को चैतन्यता, सत्य और जीवन के रहस्यों से साक्षात्कार होने के कारण बुद्ध की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार देखें तो अपने को जानने की यह तपस्या और क्रिया बाद में भी तथा भविष्य में भी निरंतर चलती रहेगी। यदि बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ें तो उनके अनुसार मनुष्य को सदैव शुभ कर्म करते हुए अशुभ तथा पाप कर्मों से विरक्त रहना चाहिए। यदि आदमी शुभ कर्म करे तो उसे उन्हें बार-बार करना चाहिए, उसी में चित्त लगाना चाहिए क्योंकि शुभ कर्मों का संचय सुखकर होता है। जिस काम को करके आदमी को पछताना न पड़े और जिसके फल को वह आनंदित मन से भोग सके, उसी काम को करना श्रेयस्कर है। महात्मा बुद्ध का मानना था कि उच्च चरित्र, शील एवं सदाचार की सुगंध चन्दन, तगर तथा मल्लिका जैसे फूलों की सुगंध से भी बढ़कर होती है। मनुष्यों को चाहिए कि वे पाप कर्म न करें, प्रमाद से बचें और किसी भी मनुष्य की धन-संपत्ति पर कुदृष्टि न रखें। धन की वर्षा होने भी आदमी की कामना की पूर्ति नहीं होती है। बुद्धिमान आदमी जानता है कि कामनाओं की पूर्ति में अल्प स्वाद है और दुख है। इसी प्रकार लोभ से दुःख पैदा होता है, लोभ से भय पैदा होता है।

जो व्यक्ति लोभ से मुक्त है उसके लिए न दुःख है न भय है। जो शीलवान है, जो प्रज्ञावान है, जो न्यायवादी है, जो सत्यवादी है तथा जो अपने कत्र्तव्य को पूरा करता है उससे लोग प्यार करते हैं। वाणी से बुरा वचन न बोलना, किसी को कोई कष्ट न देना, विनयपूर्वक नियमानुसार संयत रहना यही बुद्ध की देशना है। बुद्ध अहिंसा में विश्वास रखते थे, इसलिए वे न जीव हिंसा करो न कराओ के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में वर्णित है कि आदमी को चाहिए कि क्रोध को अक्रोध से जीतें, बुराई को भलाई से जीतें, लोभ को उदारता से जीतें और झूठ को सच्चाई से जीतें। सत्य बोलें, क्रोध न करें एवं कम होने पर भी दान करें। आदमी को चाहिए कि क्रोध का त्याग कर दे, अभिमान को छोड़ दे और सब बंधनों को तोडक़र ईश्वर की शरणागति हो ले। शांत आदमी जय-पराजय की चिंता छोडक़र सुखपूर्वक सोता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को अपने मन, वचन और कर्म से यह संकल्प लेना श्रेयस्कर रहेगा कि हे ईश्वर! अगर तू कहीं है तो मुझे इतनी शक्ति जरूर देना कि मैं, महात्मा बुद्ध के बताए गए आदर्शों का पालन दृढ़ता से कर पाऊं। बौद्ध धर्म दुनिया का पहला ऐसा विश्व धर्म है जो अपने जन्मस्थान से निकलकर विश्व में दूर दूर तक फैला। आज विश्व के 20 से अधिक देशों में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक या प्रमुख धर्म के रूप में है। विश्व में लाओस, कम्बोडिया, भूटान, थाईलैण्ड, म्यांमार और श्रीलंका ये छह देश 'अधिकृत' बौद्ध देश हैं, क्योंकि इन देशों के संविधानों में बौद्ध धर्म को राजधर्म या राष्ट्रधर्म का दर्जा प्राप्त है। आज भौतिकतावाद के जमाने में प्रायः हमारा मन और चित्त अशांत रहता है, ऐसे समय में महात्मा बुद्ध के उपदेश हमें मानसिक शांति और अभय प्रदान करते हैं। वस्तुतः मनुष्य को सभी शारीरिक एवं मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाना ही सभी धर्मों का मूल है।

हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि, 'धार्यते इति धर्मः'।

इस प्रकार से धर्म की व्युत्पत्ति संस्कृत के 'धृ' धातु से हुई है जिससे धर्म शब्द बना है। जिसका अर्थ धारण करना होता है, जो सबको धारण करे, जो सबका आधार हो वह धर्म है। साधारण शब्दों में धर्म के बहुत से अर्थ हैं जिनमें से कुछ हैं : कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण, सद्गुण, प्रेम, दयालुता और त्याग। आज मानव मात्र को इन्हीं सद्गुणों को अपने चरित्र में उतारने की महती आवश्यकता है, तभी यह पृथ्वी और सुंदर बनेगी और लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रेमपूर्वक सुंदर जीवन जी सकेंगे। बुद्ध की शिक्षाएं अतीत में प्रासंगिक थीं, वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगी।

संपादक की कलम से

कौनसे 'वाले' मुख्यमंत्री

हिमाचल में चुनाव की मासूमियत में मुद्दों के जख्म धोए जा रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के खाते में केंद्र सरकार का कत्र्तव्य और इधर हिमाचल की बेडियों में आर्थिक संसाधनों की किफायत में गारंटियों का मसौदा। नेता पूछ रहे हैं, क्या जनता भी पूछेगी। जो वंदेभारत से अंब-अंदौरा पहुंच रहे, उन्हें चुनाव बता रहा है कि हमीरपुर रेल के राग में विरह कितनी और विराग कितना। सवाल मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने उछाला है, तो विकास के धरती पुत्र अनुराग ठाकुर को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। क्या यही प्रश्न केंद्र में कांग्रेस के शिलालेख लिखते रहे आनंद शर्मा से पूछा जाएगा कि रेल की इबारतों में उनका योगदान कितना है। कहना न होगा कि रेल विस्तार की शून्यता में दक्षता ढूंढते-ढूंढते हमने ऊना रेल का सिंहासन बना लिया, लेकिन कांगड़ा घाटी रेल पर किससे पूछें। क्या शांता कुमार के बयानों की खाल हटा कर देखें कि 'टॉय ट्रेन' की पटरियां चौड़ी करने के लिए उनके प्रयत्नों का पतन क्यों हुआ। क्या किशन कपूर या इंदु गोस्वामी से पूछें कि जम्मू को निकली वंदेभारत कब हिमाचल के नाम पर पठानकोट में स्टॉप लगाएगी। एक नई रेल लाइन की पड़ताल में सारी राजनीति का केंद्र हमीरपुर या ऊना ही क्यों। कभी पवन बंसल ने कांग्रेस की सत्ता में रेल पर अपनी सरकार का मार्ग प्रशस्त करते हुए बजट भाषण के सुर हिमाचल से मिलाए थे। आश्चर्य यह कि तब पालमपुर और धर्मशाला के बीच रेल मार्ग का अकल्पनीय सपना उंडेल दिया गया, जबकि कांगड़ा में रेल सेवा के व्यावहारिक पक्ष को आज तक अनदेखा किया जा रहा है। हमने इन्हीं कालमों में हिमाचल की कनेक्टिविटी को लेकर रेल, वायु और सडक़ मार्गों के स्वाभाविक गलियारों के बारे में बार-बार स्पष्ट किया है। इसमें दो राय नहीं कि हिमाचल में रेल विस्तार पठानकोट से नहीं ऊना तक पहुंची ट्रेन के मार्फत होगा।

हवाई सेवाओं का विस्तार कांगड़ा एयरपोर्ट के माध्यम से होगा, जबकि सडक़ मार्गों का केंद्र बिंदु हमीरपुर में स्थापित होगा। हमारा यह कथन साबित होगा बशर्ते ऊना से अंब-अंदौरा पहुंची ट्रेन आगे चलकर ज्वालाजी पहुंचे तथा प्रस्तावित कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार संभव हो। जाहिर तौर पर ऊना रेल परियोजना के लिए प्रेम कुमार धूमल के बाद अनुराग ठाकुर के प्रयास काफी हद तक प्रशंसनीय माने जाएंगे, लेकिन अंब-अंदौरा से आगे कांगड़ा के सांसदों को भी प्रयास करना चाहिए था, लेकिन यहां दिशाविहीन माहौल में न शांता सफल हुए और न ही किशन कपूर, बल्कि वर्तमान संसदीय चुनाव में न आनंद शर्मा के पास रेल के लिए कोई वक्तव्य है और न ही भाजपा के उम्मीदवार राजीव भारद्वाज के लिए कांगड़ा घाटी रेल का सपना कोई मायने रखता है। इस दिशा में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार की रूपरेखा में पर्यटन को नई आशा और कनेक्टिविटी को भरोसा दिलाया है। हिमाचल में चुनाव भले ही विकास पर नहीं लड़े जाते, लेकिन जनता जल व विद्युत आपूर्ति के साथ-साथ सडक़ निर्माण को लेकर संवेदनशील रही है। यही वजह है कि हिमाचल में अगर शांता पानी वाले मुख्यमंत्री बने, तो प्रेम कुमार धूमल सडक़ वाले मुख्यमंत्री साबित हुए। जयराम ठाकुर ने निवेश वाले मुख्यमंत्री बनने की कोशिश की है और ड्रग बल्क पार्क तथा मेडिकल डिवाइस पार्क हासिल करके वह खुद को प्रमाणित कर पाए हैं। ऐसे में अब अनुराग ठाकुर और सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने-अपने प्रदर्शन की लिखावट से ही साबित कर पाएंगे कि वे कौनसे 'वाले' मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री हैं। अगर कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार संभव होता है, तो निश्चित रूप से सुक्खू हवाई यात्राओं वाले मुख्यमंत्री साबित होंगे। दूसरी ओर अनुराग ठाकुर अगर अंब-अंदौरा तक पहुंची रेल का मुख वाया कहीं से भी ज्वालाजी से जोड़ पाते हैं, तो वह रेल वाले पहले हिमाचली केंद्रीय मंत्री होंगे। यह इसलिए कि ज्वालामुखी से आगे यह ट्रेन कांगड़ा, बिलासपुर और मंडी तक पहुंच सकती है।

राय

नाबालिग हत्यारा भी मासूम!

पुणे में एक बेहद त्रासद हादसा हुआ है, जिसने समाज, कानून और मान्यताओं को बेनकाब कर दिया है। बड़े बाप की औलाद होना पाप नहीं है, लेकिन बिगड़ैल और हत्यारा तक होना आपराधिक है। पुणे में एक 17 वर्षीय नाबालिग, बिगड़ैल किशोर ने दो होनहार साफ्टवेयर इंजीनियरों को 2 करोड़ रुपए की कार से कुचल कर मार डाला। करीब 25 वर्षीय जिंदगियों पर एकदम विराम लग गया। दो घरों के चिराग बुझ गए, लिहाजा उनके दुख और सदमे को महसूस ही किया जा सकता है, लेकिन समाज, जेल, कानून उस नाबालिग को 'मासूम' ही मान रहे हैं, क्योंकि वह 18 साल का नहीं था। जेल में उस 'हत्यारे नाबालिग' से सडक़ दुर्घटना पर 300 शब्दों का निबंध लिखवाया जाता है और करीब 15 घंटे में अदालत से उसकी जमानत भी हो जाती है! संविधान के किस पन्ने पर और किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि कोई किसी की जान लेने का जघन्य अपराध करे, लेकिन निबंध लिखवा कर ही उसे जमानत दे दी जाए? कानून वाकई अंधा होता है, क्योंकि वह सिर्फ सबूत देखता है, हकीकत को नहीं जानता! नबालिग हत्यारे के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, कार का पंजीकरण नहीं था, लेकिन वह एक बेशकीमती कार दनदनाते हुए चला रहा था, क्योंकि वह 600 करोड़ रुपए की कंपनी के मालिक, बिल्डर का बेटा था! क्या कानून के सामने ये साक्ष्य नहीं थे? क्या अमीर, बिल्डर बाप बराबर का दोषी नहीं है, जिसने 2 करोड़ रुपए की कार नाबालिग बेटे को खरीद कर दी? उस उच्छृंखल बालक ने सार्वजनिक सडक़ को 'बंगले का आंगन' समझ लिया और दो युवाओं को कुचल कर मार दिया। नाबालिग आरोपित को हिरासत में पिज्जा, बर्गर और बिरयानी आदि भोज परोसे गए, तो वह खातिरदारी भी 'बड़े बाप की औलाद' होने के कारण की गई। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि नाबालिग अपराधी ने कार से दो युवा इंजीनियरों को कुचलने से पहले पब, बार में करीब दो घंटे तक, दोस्तों के साथ, खूब शराब पी, जिसका बिल 48,000 रुपए आया और भुगतान भी नाबालिग के क्रेडिट कार्ड से किया गया।

क्या बैंक नाबालिगों के क्रेडिट कार्ड भी बनाते हैं? गंभीर सवाल तो यह है कि मेडिकल परीक्षण में शराब पीने का सच क्यों नहीं सामने आया? क्या डॉक्टर भी बड़े बाप के सामने 'बिक' गए? उस त्रासद हादसे के बाद यह तथ्य सामने आया है कि उस नाबालिग ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, लिहाजा दोस्तों और पब वालों को भी हिरासत में लिया गया है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के न्याय पर तरस आता है कि उसने हत्या की सजा निबंध लिखना ही तय की! क्यों न इसे भी संविधान में जोड़ लिया जाए? यही कारण है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस को हस्तक्षेप कर पुलिस आयुक्त को निर्देश देने पड़े। अब उच्च न्यायालय में नाबालिग पर केस बालिग मान कर ही चलाया जाएगा। हमें भी अदालत के आदर्श न्याय का इंतजार रहेगा। यह कोई इकलौता मामला नहीं है। एक मामले में बीएमडब्ल्यू कार से तीन पुलिसकर्मी मार दिए गए थे। अपराधी की अमीरी ने चश्मदीदों को 5-5 करोड़ रुपए की घूस देकर उनकी सच्चाई ही खरीद ली थी, लेकिन बाद में किसी परम शक्ति ने ही सारे भेद खोल दिए और उन ऐयाश अमीरों को सजा हुई। राजधानी दिल्ली में नशेडियों ने कार फुटपाथ पर सोए 'बेचारों' पर ही चढ़ा कर उन्हें कुचल दिया। अदालत में ये दलीलें भी दी गईं कि क्या फुटपाथ सोने के लिए होता है? बहरहाल देश में लाखों सडक़ दुर्घटनाएं होती हैं और लाखों ही जिंदगी गंवाते हैं, लेकिन ऐसे मामले बेशुमार दौलत, नव अमीरी और गरीबों को कीड़े-मकौड़े समझने की संस्कृति की देन ही हैं।

नाकाबिल ही नाकाबिल

क्या कभी वे दिन भी आ जाएंगे, जबकि भरपूर मेहनत करने वाला अपमानित, लांछित और निर्वासित होकर किसी विरोधी धरना प्रदर्शन करने के काबिल भी नहीं रह जाएगा? पहले की तरह ही छुटभैये सभी अदब कायदे तोड़ कर पहचान के शिखर पर बैठ कर अब भी मुस्कराते रहेंगे। ऐसा सवाल पूछने वाले आजकल उजबक कहलाते हैं। वे दिन बीत गए, जब आत्मविश्वास से भरे हुए दृढ़-प्रतिज्ञ लोग रुक कर अजनबी धरती के किसी भी कोने पर पांव टिका कर कह देते थे कि 'हम जहां खड़े हो गए, कतार वहां से ही शुरू हो जाती है।' आज अंतरराष्ट्रीय मानक संस्थानों से लेकर भ्रष्टाचार को मापने वाली ट्रांस्पेरेंसी अंतरराष्ट्रीय संस्थान जैसी संस्थाएं भी आह भर कर उद्दाम जोश से भरे इन लोगों को कह देती हैं कि 'होगी जनाब, आप में कोई भी नई कतार शुरू करने की ताकत, परन्तु पहले यह बताइए कि आपके सिर पर यह कतार शुरू करने के लिए किसी गॉड फादर का हाथ है?' हमने 'मारिया पिजो' के उपन्यास का नाम 'गॉडफादर' सुना था कि जिसके एक इशारे पर एक नई कतार ही शुरू नहीं होती थी, पूरी चलती बिसात ही उलट कर नई बिसात बिछा दी जाती थी। हम जानते थे कि गॉडफादर एक अंग्रेजी शब्द है। 'आप हिन्दी में लिखने का दम भरते हैं, इसका हिन्दी में सटीक और समानार्थक शब्द तलाश करके लाइए', हमें कहा गया।

हम ठहरे मेहनती आदमी, समानार्थक शब्द की तलाश में जुट गए, लेकिन इसी अंग्रेजी शीर्षक के पितृसंरक्षकों ने इस बीच हमें खेल के वृत्त से बाहर कर दिया। उधर कतार शुरू हो गई, जुम्मा-जुम्मा आठ दिन के प्रवेश वाले भद्र चहेतों से, जिन्हें हथेली पर सरसों जमाने की आदत हो गई है। भ्रष्टाचार मापक संस्थानों के मापकों या मसीहाओं ने हमारी नादानी का मातम मनाते हुए समझाया, 'अरे भई, इतना भी नहीं जान पाए कि यहां पर एक ही स्थान पर खड़े-खड़े तरक्की की घोषणा हो जाती है।' लोग जहां से चलते हैं, उसी वृत्त में घूमते हुए फिर उसी बिन्दू पर ठिठक जाते हैं, और घोषणा हो जाती है कि देखो, इस बीच जमाना कयामत की चाल चल गया।

महामारियों के विकट प्रकोप में तुम आम आदमी की दुर्दशा का रोना रोते रहे, और उससे हुई एक प्रतिशत लोगों की तरक्की का तनिक जिक्र भी नहीं किया कि जिनकी आय इस बीच सौ प्रतिशत बढ़ गई है। अब भला आम आदमी का जिक्र करके अपना मुंह कसैला क्यों करते हो, क्यों न चुनिंदा लोगों की बातें करें? आम लोग तो पहले जैसे थे, आज भी वैसे ही हैं। पहले भी भूखे, बेघर और बेकार थे, आज भी वैसे ही हैं। उनके अपमानित और लांछित हो जाने की चिंता क्यों करते हो? इस भाग्यवादी देश में नियति भी तो एक अकाट्य सत्य है।

यह दीगर बात है कि उसके भाग्य के फूटा होने का विवरण ही इन आम आदमियों को मिलता है और अभिनंदन का तरन्नुम किन्हीं शार्टकट गलियों में से निकलता हुआ दूसरों के गले में वरमाला पहना जाता है।

उन लोगों के गले में जो कभी तीन में नहीं थे और अब तेरह में भी नहीं हैं। फिर भी कुर्सी पा गए। लेकिन इस सच्चाई से चौंकना कैसा? जब दौड़ हुई ही नहीं, तब उस दौड़ में पीछे रह जाने से अपमानित और लांछित महसूस करने का क्या तुक? यह तुक भी बड़ी चीज है बन्धु! अगर वही भिड़ानी आपको आज तक आ गई होती तो आज हमें तुक से बेतुका हो जाने का अर्थ समझाने की जरूरत आपको न पड़ती। 'होता है तमाशा दिन-रात मेरे आगे' की तरह हमने हर दिन बेतुके लोगों को संगीत, कला, जीवन और समाज की सुर्खियां जीत लेने की घटनाओं में सिरमौर बनते देखे हैं। अकादमिक रूप से भी इस सत्य का परिचय बहुत से भ्रष्टाचार सर्वेक्षण के आंकड़े हमें बता देते हैं।

सुरेश सेठ

विचार

मोको कहां ढूंढे रे बंदे...

हम किसी भी धर्म, संप्रदाय, मत को मानते हों, हमारे इष्ट देव कोई भी हों, उसे बदलने की जरूरत नहीं है। बदलना है सिर्फ अपना नजरिया, अपना जीवन, अपना लाइफस्टाइल। इससे ही सब बदल जाएगा। सहज संन्यास मिशन के हम सब अनुयायियों का मानना है कि यदि हम जीवन का सम्मान करें, अपने मन को बुराइयों से दूर रखें, अपनी वाणी से किसी को चोट न पहुंचाएं, बुराइयों को दूर करने के लिए उचित प्रयत्न करें, अपने विचारों को अनियंत्रित न होने दें, सबकी भलाई के लिए काम करें, मन में भक्ति का भाव रखें, तो हमारे लिए अंतिम सत्य तक पहुंचना बहुत कठिन नहीं होगा और हमारा जीवन सरल हो जाएगा और फिर हमें परमात्मा की खोज के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा क्योंकि फिर हम खुद ब्रह्मस्वरूप हो जाएंगे'

जैन धर्म का क्षमा-वाणी पर्व एक ऐसा नियम है जो सचमुच बहुत अच्छा है। पूरे साल भर में जाने-अनजाने हमने कभी कोई गलती की हो, किसी का अपमान हो गया हो, किसी को चोट पहुंचाई हो, किसी का नुकसान हो गया हो तो इस पर्व वाले दिन बिना शर्त माफी मांगने का प्रावधान है। कितना सुंदर, कितना बढिया। सामने वाले ने चाहा या नहीं चाहा, पर हमने विनम्र होकर माफी मांग ली। गलती हुई या नहीं हुई, चाहे अनजाने में ही हो गई हो, तो भी माफी मांग ली, दोनों का दिल साफ हो गया, रिश्ते सुधर गए, दिल हल्का हो गया और प्रेम बना रहा। जैन धर्म के अनुयायी इस दिन एक-दूसरे को 'मिच्छामि दुक्कड़म' बोलते हैं। अगर यह सिर्फ एक औपचारिकता ही न हो तो इससे रिश्तों की मजबूती का इससे बढिया और कोई साधन है ही नहीं। जब हम मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार हों कि बिना किसी वजह के माफी मांग लेनी है कि शायद कोई गलती हुई हो, और हम सब इतने विनम्र हो जाएं तो सारे झगड़े ही खत्म। मिच्छामि दुक्कड़म प्राकृत भाषा का शब्द है। संस्कृत के एक वाक्यांश से यह बना है, जो है 'मिथ्या मे दुष्कृतम्' जिसका मतलब है कि यदि मैंने कोई दुष्कृत्य किया हो, कुछ भी बुरा किया है तो वह मिथ्या हो जाए, खत्म हो जाए, बीजरहित हो जाए, ताकि दोबारा कभी न हो। जब हम इतने विनम्र हो गए तो हम सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक हो गए। जैन धर्म अहिंसा का धर्म है, और हम सब जानते हैं कि हिंसा कई तरह से हो सकती है, मसलन कायिक हिंसा, यानी, शारीरिक हिंसा, किसी को मारना या मार डालना, शारीरिक चोट पहुंचाना।

दूसरा है वाचिक हिंसा, यानी, किसी का अपमान कर देना, किसी को ऐसा कुछ कह देना कि उसका दिल दुख जाए, वाणी से किसी को चोट पहुंचाना, किसी को गाली दे देना, लंगड़ा, लूला, अंधा, काना आदि कह देना, ये है वाचिक हिंसा, और हिंसा की तीसरी किस्म है मानसिक हिंसा। अगर हमने मन में ठान लिया है कि कोई दूसरा व्यक्ति, चाहे वह पति हो, पत्नी हो, बेटा या बेटी हो, अधीनस्थ कर्मचारी हो, नौकर-नौकरानी हो, और हम यह सोच लें कि वह हमारे हिसाब से ही जियेगा तो यह मानसिक हिंसा है। हम किसी दूसरे को बदलना चाहते हैं, यह मानसिक हिंसा है, और जब हमने हिंसा पूरी तरह से छोड़ दी तो हम आध्यात्मिक हो गए। जब हम विनम्र हो गए, अहिंसक हो गए, प्रेममय हो गए तो हम शुद्ध हो गए और हमने परमात्मा को पा लिया। फिर हमें कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं है, फिर हमने बड़ी से बड़ी तीर्थ यात्रा का, पूजा का फल पा लिया। फिर हम किसी पूजा स्थल के मोहताज नहीं रह गए, कोई और जप-तप इसके मुकाबले में छोटा ही है। जब हम प्रेममय हो गए, हमने प्रेम के अढ़ाई अक्षर जीवन में उतार लिए तो फिर संत कबीर की वाणी सच्ची हो गई। संत कबीर फरमाते हैं, 'मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। ना मैं त्रिकुटी भंवर में, सब स्वासों के स्वास में। खोजी होए, तुरत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, मैं तो हूं विश्वास में।' यह सच है कि अध्यात्म की असली सीढ़ी है निश्छल प्रेम, हर किसी से प्रेम, बिना कारण, बिना आशा के हर किसी से प्रेम।

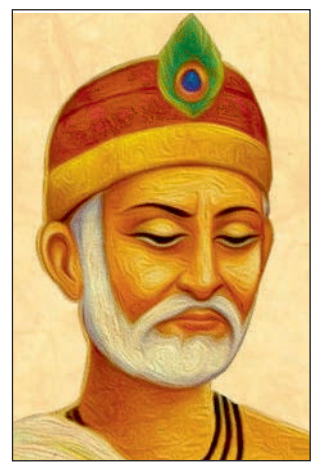

मानवों से ही नहीं, पशु-पक्षियों और पेड़-पौधों से भी प्रेम, जीवित लोगों से ही नहीं, जीवन रहित मानी जाने वाली चीजों से भी प्रेम। एक बार जब हम प्रेममय हो गए तो आध्यात्मिकता की गहराइयों में, या यूं कहिए कि ऊंचाइयों में जाने के काबिल हो जाते हैं। यह अध्यात्म की सबसे ऊंची पायदान है, और इसके बाद कल्याण ही कल्याण है, निर्वाण है, मोक्ष है, मुक्ति है। आध्यात्मिकता का अर्थ है कि हम सब के प्रति दया का भाव रखें, प्रेम का भाव रखें, जहां तक संभव हो, निस्वार्थ भाव से सहायता करें। हम खुद को बदलें, हमारे अंदर के परिवर्तन से ही सब कुछ बदलेगा। हमारा नजरिया बदलेगा तो हम बदलेंगे। हम बदलेंगे तो परिवार बदलेगा, समाज बदलेगा, देश बदलेगा, दुनिया बदलेगी। जब तक हम खुद नहीं बदलेंगी, हमारी दुनिया नहीं बदलेगी। हमारे संपर्क में आने वाले लोग हमारी दुनिया हैं। हम बदल जाएंगे तो शायद हम उन लोगों में बदलाव ला सकेंगे जो हमारे संपर्क में आते हैं। हम ही नहीं बदले तो बाकी सब बदल भी जाए तो भी हमारे लिए वह बदलाव अर्थहीन ही रहेगा। आध्यात्मिक हो जाएं तो पूरा ब्रह्मांड हमें परमात्मा की स्तुति करता हुआ नजर आता है। 'सहज संन्यास मिशन' की धारणा है कि हमारा शरीर ही मंदिर है, हमारा कत्र्तव्य ही पूजा है और चढ़ावा चढ़ाने के लिए किसी पूजा स्थल पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो कुछ करूं, वह परमात्मा को अर्पण करके करूं। 'कर करनी, कर जोड़ कर' को इसी भाव में समझना चाहिए। कर करनी, यानी जो भी करें, कर जोड़ कर करें, हाथ जोड़ कर करें, परमात्मा को नमस्कार करके करें। संत रविदास जी ने क्या खूब ही कहा है कि 'मन चंगा, तो कठौती में गंगा', मन शुद्ध हो आपके बर्तन में पड़ा पानी भी साधारण नहीं रह जाता, वह गंगाजल जितना निर्मल और पवित्र हो जाता है। दिन भर काम करते हुए हम इधर-उधर जाते हैं, वही परमात्मा की परिक्रमा है, मेरा हर काम परमात्मा की पूजा है। मैं ही परमात्मा हूं, और इस जगत का हर जीव-जंतु परमात्मा का ही अंश है।

अब जब हर कोई परमात्मा का अंश है और मेरा हर काम परमात्मा की पूजा है तो मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं, किसी को धोखा कैसे दे सकता हूं, फरेब कैसे कर सकता हूं? यही निष्काम कर्म है, यही सहज संन्यास है। वस्तुतः निष्काम कर्म ही सहज संन्यास है। सहज संन्यास की खासियत ही यही है कि इसके लिए हमें अपना धर्म बदलने की आवश्यकता नहीं है। हम किसी भी धर्म, संप्रदाय, मत को मानते हों, हमारे इष्ट देव कोई भी हों, उसे बदलने की जरूरत नहीं है। बदलना है सिर्फ अपना नजरिया, अपना जीवन, अपना लाइफस्टाइल। इससे ही सब बदल जाएगा। सहज संन्यास मिशन के हम सब अनुयायियों का मानना है कि यदि हम जीवन का सम्मान करें, अपने मन को बुराइयों से दूर रखें, अपनी वाणी से किसी को चोट न पहुंचाएं, बुराइयों को दूर करने के लिए उचित प्रयत्न करें, अपने विचारों को अनियंत्रित न होने दें, सबकी भलाई के लिए काम करें, मन में भक्ति का भाव रखें, तो हमारे लिए अंतिम सत्य तक पहुंचना बहुत कठिन नहीं होगा और हमारा जीवन सरल हो जाएगा और फिर हमें परमात्मा की खोज के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा क्योंकि फिर हम खुद ब्रह्मस्वरूप हो जाएंगे।

उड़ान के दौरान फ्लाइट में क यों लगते हैं झटके, कितना खतरनाक हो सकता है इन-फ्लाइट टर्बुलेंस?

परिवहन विशेष न्यूज

टर्बुलेंस वैसे तो उड़ानों के दौरान होने वाली सामान्य घटना है और आमतौर पर यह खतरनाक नहीं होता। आधुनिक विमानों को भी इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो हर तरह के टर्बुलेंस को आसानी से झेल लें। मौजूदा विमानों में ऐसे सेंसर्स भी लगे होते हैं जो पहले ही इसका पता लगा लेते हैं और पायलट पहले ही यात्रियों को चेतावनी दे सकता है।

नई दिल्ली। अशांति क्या है, अगर आपने भी कभी विमान यात्रा की है तो आप टर्बुलेंस (Turbulence) नाम के शब्द से जरूर परिचित होंगे। जी हां, उड़ान के दौरान कई बार विभिन्न वजहों से विमान में झटके लगते हैं या विमान हिचकोले खाने लगता है, जिसे टर्बुलेंस कहा जाता है। इसका अनुभव थोड़ा डरावना होता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। टर्बुलेंस हवाई यात्रा का एक सामान्य हिस्सा है। यह ज्यादातर यात्रियों को कभी न कभी अनुभव होता ही है। हालांकि कई बार यह इतना ज्यादा होता है कि जानलेवा भी साबित हो सकता है।

ऐसी ही एक घटना 21 मई को सिंगापुर एयरलाइंस के एक विमान के साथ हुई। लंदन से सिंगापुर जा रहे सिंगापुर एयरलाइंस (Singapore Airlines) के एक विमान को मंगलवार 21 मई 2024 को इतने जबरदस्त टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा कि उसकी बैंकॉक में इमरजेंसी लैंडिंग तक करवानी पड़ी। टर्बुलेंस इतना जबरदस्त था कि विमान बहुत तेज हिचकोले खाने लगा। इससे विमान में बैठे एक बुजुर्ग यात्री की मौत तक हो गई जबकि दर्जनों अन्य यात्री घायल हो गए।

टर्बुलेंस क्या है?

टर्बुलेंस या इन फ्लाइट टर्बुलेंस हवा के प्रवाह में दबाव और गति में अचानक परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली स्थिति है, जिससे विमान को उड़ान के दौरान हवा में झटके लगते हैं और वह हिलने-डुलने लगता है। टर्बुलेंस की वजह से विमान में हल्के झटके से लेकर कभी-कभी बहुत तेज और लंबे झटके भी महसूस हो सकते हैं।

इन कारणों से होता है टर्बुलेंस

- खराब मौसम टर्बुलेंस की सबसे बड़ी वजह होती है। तूफान, तेज़ हवाएं और वायुमंडल में अस्थिरता इसका मुख्य कारण होती हैं।
- पहाड़ों और ऊंची चोटियों के पास हवा का बहाव अस्थिर हो सकता है, जिससे विमान को झटके लग सकते हैं।
- जेट स्ट्रीम्स (Jet Streams) भी टर्बुलेंस की बड़ी वजह हो सकते हैं। ये तेज हवाओं की संकरी धाराएं होती हैं, जो ऊपरी वायुमंडल में पाई जाती हैं। इनको पार करते समय विमान में अचानक झटके लग सकते हैं।

कितना खतरनाक है टर्बुलेंस?

टर्बुलेंस वैसे तो उड़ानों के दौरान होने वाली सामान्य घटना है और आमतौर पर यह खतरनाक नहीं होता। आधुनिक विमानों को भी इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो हर तरह के टर्बुलेंस को आसानी से झेल लें। मौजूदा विमानों में ऐसे सेंसर्स भी लगे होते हैं, जो पहले ही इसका पता लगा लेते हैं और पायलट पहले ही यात्रियों को चेतावनी दे सकता है या फिर हालात को देखते हुए उड़ान का रास्ता भी बदल सकता है। हालांकि, कभी-कभी यह इतना तेज होता है कि इसकी वजह से विमान में सीट के ऊपर बने सामान रखने की जगह से सामान गिरने या यात्रियों को चोट लगने जैसी घटना भी हो जाती है। ऐसा कुछ सिंगापुर एयरलाइंस के उस विमान के साथ हुआ जिसमें एक वृद्ध यात्री की मौत हो गई।

टर्बुलेंस के दौरान खुद को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें?

- टर्बुलेंस के दौरान खुद को सुरक्षति रखने के लिए सबसे पहला कदम है सीट बेल्ट लगाए रखना। उड़ान के दौरान और लैंडिंग के समय हर वक्त अपनी सीट बेल्ट बांधे रखें।
- उड़ान के दौरान जब भी कैप्टन सीट बेल्ट लगाने का संकेत दें, तो तुरंत अपनी सीट पर बैठ जाएं और सीट बेल्ट लगा लें। अगर पायलट बहुत तेज टर्बुलेंस की चेतावनी दे तो सिर को सीट के हेडरेस्ट से सटा लेना चाहिए।
- टर्बुलेंस के दौरान विमान के क्रू मेम्बर्स आपको सुरक्षित रहने के निर्देश देंगे, जिनका पालन आपको करना चाहिए।

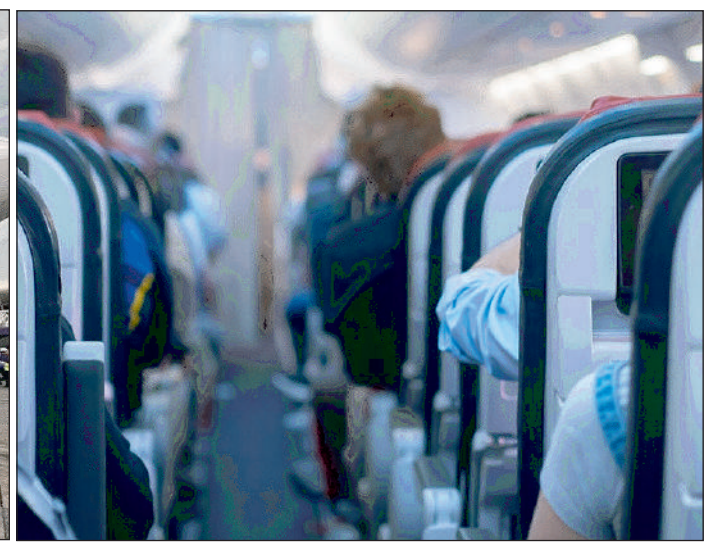

10 साल में 8 ट्रिलियन डॉलर का हुआ निवेश: ये आजादी के बाद से हुए कुल निवेश के आधे से ज्यादा

जीडीपी अनुपात के मुकाबले निवेश की बात करें तो यह 2011 में चरम था और यह तब तक कम रहा जब तक कि कोरोना के कारण हुए व्यवधान ने सप्लाई चेन को प्रभावित नहीं किया। हालांकि महामारी के बाद सुधार और सरकारी व्यय के माध्यम से बड़े पैमाने पर निवेश की वापसी हो रही है। वैश्विक स्थिति भले ही ठीक नहीं हो लेकिन भारत का आधार मजबूत बना हुआ है।

नई दिल्ली। पिछले एक दशक में आठ ट्रिलियन डॉलर का सार्वजनिक और निजी निवेश किया गया है। यह देश की आजादी के बाद से किए गए निवेश के आधे से अधिक है। डीएसपी एसेट मैनेजर्स के मुताबिक, 1947 में देश की आजादी के बाद से अब तक विभिन्न निवेश पर 14 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए गए हैं। इसमें परिवारों द्वारा आवास पर खर्च, सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के निर्माण पर खर्च और निजी पूंजी व्यय शामिल है।

वहीं सरकार ने पिछले 10 सालों में नए निवेश पर आठ ट्रिलियन डॉलर का खर्च किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार अपने प्रत्येक वार्षिक बजट में पूंजीगत व्यय आवंटन को बढ़ाती रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत निवेश को लेकर होने वाली हिचक से बाहर निकल आया है।

जीडीपी अनुपात के मुकाबले निवेश की बात करें तो यह 2011 में चरम था और यह तब तक कम रहा जब तक कि कोरोना के कारण हुए व्यवधान ने सप्लाई चेन को प्रभावित नहीं किया। हालांकि महामारी के बाद सुधार और सरकारी व्यय के माध्यम से बड़े पैमाने पर निवेश की वापसी हो रही है। वैश्विक स्थिति भले ही ठीक नहीं हो, लेकिन भारत का आधार मजबूत बना हुआ है।

रिपोर्ट में भारत के शेयर बाजारों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि भारत अब उभरते बाजारों में दूसरा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। उभरते बाजारों में भारत की हिस्सेदारी 2020 में 7.8 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान में 17.7 प्रतिशत हो गई है। इस वृद्धि का श्रेय मुख्य रूप से कंपनियों के बढ़े हुए लाभ, उनकी तेज विकास दर और इक्विटी सूचकांकों के लगातार प्रदर्शन को दिया जाता है।

छह सालों में NCR में बिना बिके घरों की संख्या 57 फीसदी घटी, सप्लाई पर नियंत्रण की वजह से हुआ ऐसा

परिवहन विशेष न्यूज

अन्सोल्ड होम्स आंकड़ों के अनुसार गुरुग्राम में बिना बिके आवासों की संख्या 53136 से कम होकर 33326 यूनिट रह गई है। नोएडा में बिना बिके घरों की संख्या 25669 यूनिट से 71 प्रतिशत घटकर 7451 इकाई रह गई है। देश के पश्चिमी क्षेत्र में एमएमआर और पुणे में बिना बिके घरों की संख्या में आठ प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

नई दिल्ली। पिछले छह सालों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में बिना बिके घरों की संख्या 57 प्रतिशत घटकर 86,420 यूनिट रह गई। रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी एनारॉक के मुताबिक एनसीआर में बिना बिके घरों की संख्या मार्च, 2018 तिमाही में 2,00,476 यूनिट थी, जो 31 मार्च, 2024 को घटकर 86,420 यूनिट रह गई। इस अवधि में देश के प्रमुख दक्षिणी शहरों (बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई) में बिना बिके घरों की संख्या 2018 के 1.96 लाख यूनिट से घटकर 2024 की पहली तिमाही में 1.76 लाख यूनिट रह गई।

वहीं देश के पश्चिमी क्षेत्र में एमएमआर और पुणे में बिना बिके घरों की संख्या में आठ प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। पूर्व स्थित कोलकाता में बिना बिके घरों की संख्या में 41 प्रतिशत की प्रभावशाली गिरावट दर्ज की गई।

एनारॉक के वाइस चेयरमैन संतोष कुमार ने कहा, "एनसीआर में बिना बिके घरों की संख्या में कमी के लिए डेवलपर्स द्वारा नई आपूर्ति पर नियंत्रण रखना है।" उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि एनसीआर में पिछले छह सालों के दौरान 1.81 लाख नए घर बिक्री के लिए उपलब्ध हुए। जबकि देश के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में इस दौरान 6.07 लाख और 8.42 लाख नए घर बिक्री के लिए उपलब्ध हुए।

आंकड़ों के अनुसार, गुरुग्राम में बिना बिके आवासों की संख्या 53,136 से कम होकर 33,326 यूनिट रह गई है। नोएडा में बिना बिके घरों की संख्या 25,669 यूनिट से 71 प्रतिशत घटकर 7,451 इकाई रह गई है। ग्रेटर नोएडा में बिना बिकी इन्वेंट्री 61,628 यूनिट के मुकाबले 70 प्रतिशत घटकर 18,668 यूनिट रह गई है। गाजियाबाद में भी बिना बिके घर 70 प्रतिशत घटकर 37,005 यूनिट से 11,011 यूनिट रह गए हैं। फरीदाबाद, दिल्ली और भिवाड़ी में संयुक्त रूप से मार्च, 2018 में बिना बिके घरों की संख्या 23,038 थी जो 31 मार्च, 2024 को 15,964 इकाई रह गई है।

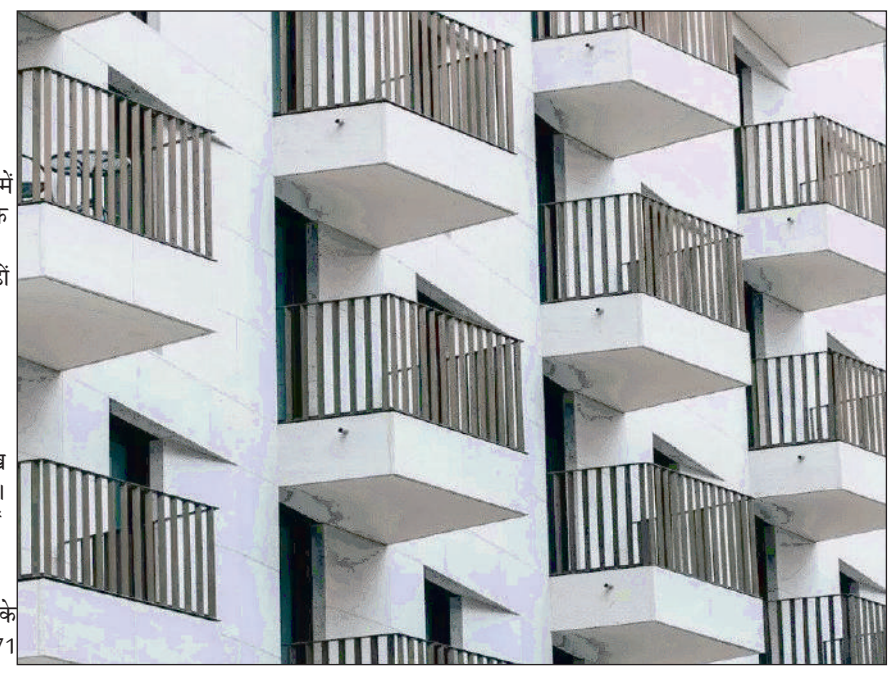

पीरामल फाउंडेशन ने सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एमोरी यूनिवर्सिटी के साथ की साझेदारी

पीरामल फाउंडेशन ने हिमाचल सरकार के साथ मिलकर सामाजिक भावनात्मक और नैतिक शिक्षण (एसईईएल) कार्यक्रम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत धर्मशाला में दलाई लामा पुस्तकालय एवं अभिलेखागार में पीरामल फाउंडेशन ने एसईई लर्निंग लॉन्च एवं प्रमाणन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य दुनिया भर में के-12 कक्षाओं में सामाजिक भावनात्मक और नैतिक साक्षरता को बढ़ावा देना है।

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक शिक्षण (एसईईएल) कार्यक्रम शुरू करने के लिए पीरामल फाउंडेशन ने राज्य सरकार के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। धर्मशाला के दलाई लामा पुस्तकालय एवं अभिलेखागार में पीरामल फाउंडेशन ने एसईई लर्निंग लॉन्च एवं प्रमाणन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस पहल की शुरुआत दलाई लामा के शिक्षा में धर्मनिरपेक्ष नैतिकता और मानवीय मूल्यों को एकीकृत करने के दृष्टिकोण से हुई है।

अमेरिका की एमोरी यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ कंटेम्पलेटिव साइंस एंड कम्पैशन-बेस्ड एथिक्स द्वारा विकसित एसईई लर्निंग, शिक्षकों और हितधारकों के लिए एक व्यापक पाठ्यक्रम और संसाधन पैकेज है। इसका मुख्य लक्ष्य दुनिया भर में के-12 कक्षाओं में सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक साक्षरता को बढ़ावा देना है।

एसईई लर्निंग के क्रियान्वयन ने शिक्षा परितंत्र को बदल दिया है, जिससे जिला, ब्लॉक, पंचायत स्तर से लेकर मास्टर फैसिलिटेटर, छात्र और सामुदायिक स्वयंसेवक तक पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यह करुणा भरे वातावरण का निर्माण करता है, फैसिलिटेटर को सशक्त बनाता है, छात्रों को समग्र कौशल से लैस करता है और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देता है।

"इस काम को करने के पीछे जो प्रेरणा है, वह मेरे इस दृढ़ विश्वास को दर्शाती है कि जब हम सभी नैतिकता के महत्व को सराहते हैं और करुणा तथा धैर्य जैसे आंतरिक मूल्यों को अपने जीवन के बुनियादी दृष्टिकोण का अभिन्न अंग बनाते हैं तो इसके दूरगामी प्रभाव होते हैं। मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है, जब बच्चे, स्कूल में अहिंसा और शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान के सिद्धांतों के परिणामस्वरूप, अपनी भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक होंगे और अपने तथा दुनिया के प्रति और व्यापक रूप से जिम्मेदारी की भावना और गहराई से महसूस करेंगे।": दलाई लामा, तिब्बती धर्मगुरु

भावनात्मक कहानियों का प्रस्तुतीकरण

इस प्रोग्राम में पीरामल फाउंडेशन की ओर से एसईई लर्निंग में ₹भावनात्मक की कहानियोंर का प्रस्तुतीकरण किया गया। इसने 6 राज्यों (जम्मू कश्मीर और लद्दाख, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओड़िशा, महाराष्ट्र और राजस्थान) में एसईई लर्निंग कार्यक्रमों की सफलता पर प्रकाश डाला, जो दिल और दिमाग दोनों पर समग्र शिक्षा के परिवर्तनकारी प्रभाव को दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों में, पीरामल फाउंडेशन ने पूरे भारत में 100,000 से अधिक स्कूलों को प्रभावित किया है।

"सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक शिक्षा (एसईई लर्निंग) को अपनाना सिर्फ एक शैक्षणिक विकल्प ही नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक अनिवार्यता है। समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध संगठनों को अपने कार्यक्रमों में सहानुभूति, लचीलापन और नैतिक निर्णय लेने को बढ़ावा देते हुए एसईई लर्निंग को शामिल करना चाहिए। पीरामल फाउंडेशन एसईई लर्निंग के जरिये, भारत में करुणा आधारित पठन-पाठन वाली स्कूल शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं समग्र विकास हासिल करने के लिए शिक्षा के साथ सामाजिक नैतिकता के संयोजन के परम पावन दलाई लामा के दृष्टिकोण से दृढ़ता से सहमत हूं।": अजय पीरामल, चेयरमैन, पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड

एसईई लर्निंग कार्यक्रम को अप्रैल 2018 में वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया गया था, जिसके तहत पीरामल फाउंडेशन और एमोरी यूनिवर्सिटी ने करुणा और लचीलेपन पर केंद्रित पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए साझेदारी की थी। यह पहल, भारत में ऐसी शिक्षा की तत्काल आवश्यकता को पूरा करती है, जो किशोरों मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों और छात्रों के बीच आत्महत्याओं की उच्च दर पर रोशनी डालती है।

शेयर बाजार ने बनाया रिकॉर्ड तो मालामाल हुए निवेशक, 4.28 लाख करोड़ रुपये बढ़ी इन्वेस्टर्स की संपत्ति

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स गुरुवार को कारोबार के दौरान 75000 के स्तर पर पहुंच गया। यह 1196.98 अंक या 1.61 प्रतिशत चढ़कर 75418.04 के नए समापन शिखर पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 1278.85 अंक या 1.72 प्रतिशत बढ़कर 75499.91 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। निवेशकों की संपत्ति में भी 428602.18 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

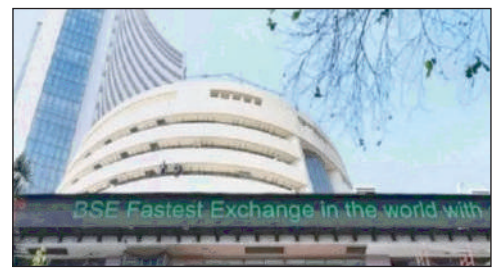

नई दिल्ली। शेयर बाजार में जारी सकारात्मक रुख के बीच निवेशकों की संपत्ति में गुरुवार को 4.28 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। सेंसेक्स और निफ्टी के सर्वकालिक शिखर को छूने शेयरधारकों की चांदी हो गई है।

शेयर बाजार ने बनाया रिकॉर्ड

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स गुरुवार को कारोबार के दौरान 75,000 के स्तर पर पहुंच गया। यह 1196.98 अंक या 1.61 प्रतिशत चढ़कर 75418.04 के नए समापन शिखर पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 1278.85 अंक या 1.72 प्रतिशत बढ़कर 75499.91 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। एनएसई निफ्टी 369.85 अंक या 1.64 प्रतिशत चढ़कर 22967.65 पर बंद हुआ। यह 395.8 अंक या 1.75 प्रतिशत चढ़कर 22993.60 पर पहुंच गया, जो कि सूचकांक का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है।

निवेशकों की बल्ले-बल्ले

निवेशकों की संपत्ति में 4,28,602.18 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई, जबकि बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 4,20,22,635.90 करोड़ रुपये (5.05 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।

कंपनियों की पूंजी पहुंची 5 ट्रिलियन डॉलर के पार

बुधवार को कारोबार बंद होने पर बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण पहली बार ऐतिहासिक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए सरकार को रिकॉर्ड 2.1 लाख करोड़ रुपये का डिविडेंट देगा, जो बजटीय अपेक्षा से दोगुना है, जिससे नई सरकार के कार्यभार संभालने से पहले राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि आरबीआई बोर्ड ने बुधवार को अपनी 608वीं बैठक में अधिशेष के हस्तांतरण को मंजूरी दी। बीएसई पर लिस्टेड सभी कंपनियों का संयुक्त बाजार मूल्यांकन पिछले साल 29 नवंबर को पहली बार 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के माइलस्टोन पर पहुंचा था। एनएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण भी गुरुवार को कारोबार बंद होने पर 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निशान को छू गया।

दो साल बाद एयर इंडिया ने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की, पायलटों को मिलेगा बोनस

एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की है। इसके अलावा, एयरलाइन ने पायलटों के लिए वार्षिक लक्ष्य प्रदर्शन बोनस की व्यवस्था भी शुरू की है। सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि वेतन में बढ़ोत्तरी का फैसला एक अप्रैल 2024 से प्रभावी होगा

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। टाटा समूह के नियंत्रण में जाने के दो साल बाद एयर इंडिया के कर्मियों के वेतन में पहली बार वृद्धि की गई है। साथ ही, एयरलाइन ने पायलटों के लिए वार्षिक लक्ष्य प्रदर्शन बोनस की व्यवस्था भी शुरू की है। सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि वेतन में बढ़ोतरी का फैसला एक अप्रैल 2024 से प्रभावी होगा, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में प्रदर्शन के आधार पर कर्मचारियों को बोनस भी दिया जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, एयर इंडिया मुख्य मानव संसाधन अधिकारी रवींद्र कुमार जीपी ने कर्मचारियों के वेतन वृद्धि और प्रदर्शन बोनस की घोषणा की। एयरलाइन के साथ अभी करीब 18 हजार कर्मचारी जुड़े हुए हैं। एयर इंडिया का नियंत्रण जनवरी 2022 में टाटा समूह के हाथों में चला गया था। जिसके दो साल बाद पहली बार इसके कर्मियों का वेतन बढ़ाया गया है। पिछले साल पुराने कर्मचारियों के अनुबंध पुनर्गठन और मुआवजा का ही काम हुआ था। सूत्रों ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए तय वेतन में वृद्धि के अलावा एयरलाइन ने कंपनी और व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर अपने पायलटों के लिए वार्षिक लक्ष्य प्रदर्शन बोनस की पेशकश की है, जो वित्त वर्ष 2024-25 से लागू होगा।

व्यावसायिक वाहनों का रोड टैक्स अब एकमुश्त करना होगा जमा, नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी...

उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता हटने के बाद नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। प्रदेश में 13 वर्षों से टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। अब बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक वाहनों का रोड समेत अन्य टैक्स एकमुश्त जमा करना होगा। चुनाव आचार संहिता हटने के बाद निजी वाहनों की तर्ज पर व्यावसायिक वाहनों से भी एकमुश्त टैक्स वसूलने की तैयारी है। इसके तहत आटो, ई रिक्शा, टेंपो और साढ़े सात टन भार वाले वाहनों के अलावा टैक्सी, मैक्सी कैब, जेसीबी और क्रेन से एकमुश्त टैक्स वसूला जाएगा।

वर्तमान में श्री व्हीलर से सालाना, तीन टन तक गुड्स से तिमाही या सालाना, टैक्सी और मैक्सी कैब से तिमाही या सालाना और यात्री वाहन से मासिक या तिमाही टैक्स वसूला जाता है। एकमुश्त टैक्स वसूलने से इनके स्वामियों पर पर लोड बढ़ जाएगा।

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने मुख्य सचिव के साथ बैठक कर एकमुश्त टैक्स को लेकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। गत वर्ष अक्तूबर में इस बाबत बात हुई थी। वहीं, टैक्स भी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। चुनाव आचार संहिता हटने के बाद शासन से इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। इसके तीन महीने बाद नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।

वहीं, विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सभी तरह के वाहनों पर 15 से 25 फीसदी तक टैक्स बढ़ाने की भी संस्तुति की गई है। पिछले 13 वर्षों से वाहनों के किसी टैक्स में कोई वृद्धि नहीं की गई है। जबकि अन्य राज्यों में पहले ही ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है।

बस व ट्रक एकमुश्त टैक्स से बाहर

परिवहन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि व्यावसायिक वाहनों में ट्रक और रोडवेज बसों को शामिल नहीं किया गया है। क्योंकि इन वाहनों पर आठ हजार से दस हजार रुपये से अधिक मासिक टैक्स आता है। ऐसे में एकमुश्त होने पर लोड बढ़ जाएगा।

'मतदान का डेटा तुरंत अपलोड करने से चुनावी माहौल बिगड़ेगा', चुनाव आयोग का अदालत में ADR की मांग का विरोध

परिवहन विशेष न्यूज

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि मतदान के बाद 48 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट पर मतदान डेटा अपलोड करने से चुनावी माहौल बिगड़ेगा। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की थी।

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण के मतदान के बाद 48 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट पर मतदान डेटा अपलोड करने की मांग को अनुचित करार दिया है। दरअसल शीर्ष अदालत में यह मांग गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन ऑप डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने उठाई थी। चुनाव आयोग ने तर्क दिया है कि ऐसा करने से चुनाव की स्थिति बिगड़ सकती है।

एडीआर ने अपनी याचिका में क्या कहा था?

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ इस मामले में एडीआर की याचिका पर सुनवाई करने वाली है। एडीआर की याचिका में इस संबंध में चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि सभी मतदान केंद्रों की जानकारी मतदान के तुरंत बाद अपलोड की जानी चाहिए। एडीआर ने यह भी मांग की है कि मतदान केंद्रों के फॉर्म 17 सी (दर्ज किए गए वोटों का खाता) की प्रतियां मतदान के तुरंत बाद अपलोड की जाएं।

डेटा अपलोड करने से चुनावी क्षेत्र में गड़बड़ी की संभावना- चुनाव आयोग

इस मामले चुनाव आयोग ने अदालत में हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में बताया गया है कि 48 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट पर मतदान डेटा अपलोड करने से पूरे चुनावी क्षेत्र में गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि छेड़छाड़ की संभावना बढ़ जाती है। हलफनामे में बताया गया है कि फॉर्म 17 सी की सार्वजनिक रूप से अपलोड नहीं किया जा सकता क्योंकि वैधानिक ढांचे में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। चुनाव आयोग ने यह दलील भी दी कि कुछ लोगों द्वारा हर बार चुनाव के समय के संदेह का माहौल बनाकर आधारहीन और झूठे आरोप लगाए जाते हैं। ऐसा इसलिए, ताकि चुनाव आयोग को बदनाम किया जा सके।

बता दें कि 17 मई को एडीआर ने शीर्ष अदालत याचिका दायर की थी। इसके बाद शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा था।

देश में हिंदू-मुस्लिम विवाद का जिम्मेदार कौन?

विपक्षी दलों का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'हिंदू-मुसलमान' कर रहे है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 10 वर्ष के लंबे कार्यकाल में कभी भी जाति या मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं किया है। परंतु सच्चाई यह है कि हिंदू-मुस्लिम विमर्श इस भूखंड पर आजादी...

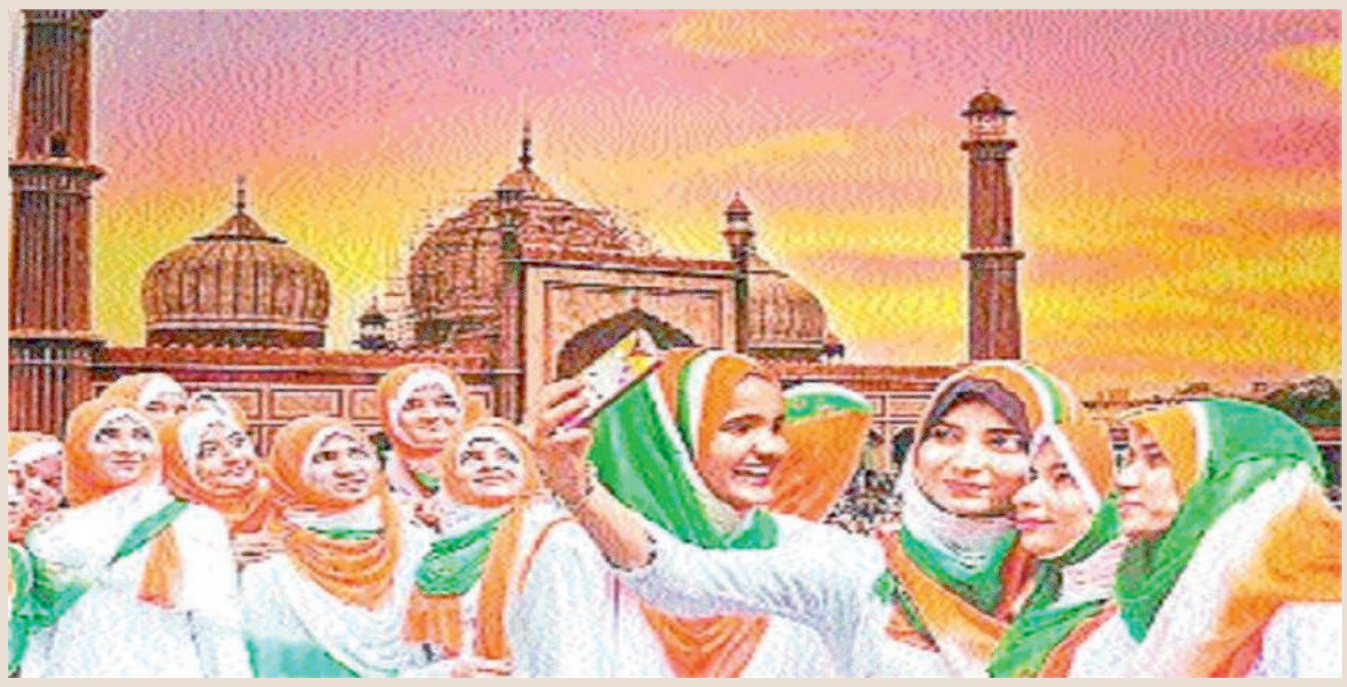

विपक्षी दलों का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'हिंदू-मुसलमान' कर रहे है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 10 वर्ष के लंबे कार्यकाल में कभी भी जाति या मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं किया है। परंतु सच्चाई यह है कि हिंदू-मुस्लिम विमर्श इस भूखंड पर आजादी के दशकों पहले से रहा है और आज भी है। दिलचस्प यह है कि मुसलमानों के नाम पर जो आरोप आज भाजपा-संघ-मोदी पर लगाए जाते हैं, वही स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस-गांधी-नेहरू के खिलाफ लगाए जाते थे। तब तथाकथित मुसलमानों के उत्पीडन का आरोप लगाने वाले अंग्रेज और वामपंथी थे। कितनी विडम्बना है कि आज वही कुत्सित काम कांग्रेस और वामपंथी कर रहे हैं। चुनाव में 'हिंदू-मुस्लिम' इसलिए भी है, क्योंकि विपक्ष का एक भाग वोट बैंक की राजनीति के अंतर्गत पूरे मुस्लिमों को गरीब-पिछड़े की संज्ञा देकर आरक्षण देने की मांग कर रहा है।

आई.एन.डी.आई.ए. के प्रमुख सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के अनुसार, ''मुस्लिमों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए।'' यह विचार पहली बार सामने नहीं आया है। कांग्रेस वर्ष 2004-14 के बीच 5 बार मुस्लिम आरक्षण देने का प्रयास कर चुकी है, जिन्हें अदालतों ने असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया। हाल ही में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के सभी मुस्लिमों को ओ.बी.सी. कोटे में शामिल कर दिया था। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में नौकरियों-शिक्षा में मुसलमानों को राष्ट्रव्यापी आरक्षण देने का वादा किया था। स्वयं कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी भी इसका समर्थन कर चुके हैं।

मामला केवल मुस्लिम आरक्षण तक सीमित नहीं है। हिंदू समाज में जातीय मतभेद को और अधिक बढ़ाने हेतु राहुल जातिगत जनगणना करके आबादी के हिसाब के राष्ट्रीय संपत्ति-संसाधनों को पुनर्वितरित करने का वादा कर रहे हैं। यदि इन मुद्दों पर देश में बहस होगी, तो स्वाभाविक रूप से हिंदू-मुस्लिम तो होगा ही। जिस प्रकार 1980 के दशक में इंदिरा गांधी ने खालिस्तानी चरमपंथी जरनैल भिंडारांवाले को आगे रखकर हिंदू-सिख संबंधों को लेकर प्राणघातक राजनीति की, ठीक उसी तरह राहुल के पिता राजीव गांधी ने वर्ष 1986 के शाहबानो मामले से 'मुस्लिम वोट बैंक' का बिगुल फूंक दिया था। तब मुस्लिम कट्टरपंथियों के समक्ष घुटने टेकते हुए तत्कालीन राजीव सरकार ने संसद में प्रचंड बहुमत के बल पर मुस्लिम महिला उत्थान की दिशा में आए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया था।

इसके बाद मुस्लिम-विरोध के कारण सलमान रुश्दी की 'सैटेनिक वर्सेज' (1988) और तसलीमा नसरीन की 'लज्जा' (1993) पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी विभाजनकारी सियासत से प्रेरित होकर वर्ष 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने घुमा-फिराकर देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का बता दिया। मुस्लिम आरक्षण/कोटा/उप-कोटा देने का प्रयास, इसी विषैली शृंखला का अगला हिस्सा है। भारतीय समाज का वंचित-शोषित वर्ग सदियों से उपेक्षित है। स्वतंत्रता के बाद देश के नीति-निर्माताओं ने उनके लिए संविधान में आरक्षण की उचित, तार्किक और आवश्यक व्यवस्था की, परंतु मुस्लिम आरक्षण से इंकार कर दिया। तब भी और आज भी मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग इस पर 'घमंड' करता थकता नहीं कि मुसलमानों का हिंदू बाहुल्य भारत पर 800 वर्षों तक राज था।

यह बखान उनके द्वारा वर्तमान समय में भी खिलजी, बाबर, औरंगजेब और टीपू सुल्तान आदि इस्लामी आक्रांताओं को 'नायक' मानने में झलकता है। यह मानसिकता 'दो राष्ट्र सिद्धांत' का बीजारोपण करके 1947 में इस्लाम के नाम पर भारत का विभाजन कर चुकी है। क्या समस्त मुस्लिम समाज को आरक्षण देने की कोशिश, देश को पुनः खंडित करने का प्रयास नहीं? क्या मोदी सरकार हिंदू-मुसलमान में फर्क करती है? पिछले 10 वर्षों में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं (पी.एम.-आवास, उज्जवला, मुद्रा, जनधन, किसान सहित) के अंतर्गत, लगभग 90 करोड़ लाभार्थियों को बिना किसी जाति, पंथ, मजहबी और राजनीतिक भेदभाव के 34 लाख करोड़ रुपया डी.बी.टी. के माध्यम से वितरित किया गया है। यही नहीं, वैश्विक महामारी कोरोना कालखंड से मोदी सरकार निःशुल्क टीकाकरण के साथ पिछले 4 वर्षों से देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रही है। इन्हीं प्रयासों से लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल चुके हैं।

फिर भी स्वयंभू सैकुलरवादी और वामपंथी भाजपा को 'मुस्लिम-विरोधी' के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में, मुस्लिम समाज के बड़े वर्ग में भाजपा विरोधी पूर्वाग्रह है, जो ब्रितानियों के दौर से चला आ रहा है।

यह सही है कि भारतीय मुसलमानों का बड़ा वर्ग आज भी विशेषकर शिक्षण मामले में पिछड़ा है। जब समाज का कोई हिस्सा शिक्षा में पीछे रह जाता है, तो उसका दुष्प्रभाव अन्य क्षेत्रों में स्वतः दिखता है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए वे कट्टरपंथी मुस्लिम उत्तरदायी नहीं, जो अपने बच्चों को इस्लाम के नाम पर मदरसों में जाने के लिए प्रेरित करते है। चूंकि मदरसे में पढने और पढ़ाने वाले अधिकांश इस्लाम को ही मानने वाले होते हैं इसलिए उनकी आकांक्षाएं, दृष्टिकोण और कत्तव्य, शेष समाज से अलग दिखते है। उदाहरणस्वरूप, जब बढ़ती जनसंख्या के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु दशकों पहले 'हम दो, हमारे दो' नारा दिया गया, तब भी मुस्लिम जनसंख्या निरंतर बढ़ती रही। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के हालिया अध्ययन के अनुसार, 1950 और 2015 के बीच जहां भारतीय मुसलमानों की आबादी 43.15 प्रतिशत तक बढ़ चुकी है, तो बहुसंख्यक हिंदुओं की हिस्सेदारी 7.82 प्रतिशत घट गई है।

इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अन्य टी.वी. साक्षात्कार में दिया विचार महत्वपूर्ण हो जाता है। उनके अनुसार, ''मैं मुस्लिम समाज के पढ़े-लिखे लोगों को कहता हूं कि आत्ममंथन करिए। सोचिए देश इतना आगे बढ़ रहा है, अगर कमी आपके समाज में महसूस होती है, तो क्या कारण हैं?... ये आपके मन में जो है कि सत्ता पर हम बिठाएंगे, हम उतारेंगे, उसमें आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो...।'' सच तो यह है कि मुस्लिम समाज के साथ उन स्वयंभू सैकुलरवादियों को भी आत्मचिंतन करना चाहिए, जो प्रगतिशील-उदारवादी मुसलमानों के बजाय कट्टरपंथी मुस्लिमों को अधिक महत्व देते हैं और उन्हें ही समाज का असली प्रतिनिधि मानते हैं।

-बलबीर पुंज

'जयललिता के निधन के बाद तमिलनाडु की सियासत में खाली जगह को भर रही भाजपा', अन्नामलाई बोले

के. अन्नामलाई ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को तमिलनाडु में दहाई अंक में मत प्रतिशत हासिल होगा और वह राज्य में तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी।

तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई ने कहा कि उनकी पार्टी अन्नाद्रमुक नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता के निधन के बाद राज्य की सियासत में खाली हुई जगह को भर रही है। उन्होंने कहा कि जयललिता बहुत बेहतर हिंदुत्व नेता थीं।

अन्नामलाई ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को तमिलनाडु में दहाई अंक में मत प्रतिशत हासिल होगा और वह राज्य में तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। आईपीएस अधिकारी से राजनेता बने अन्नामलाई ने कहा कि जयललिता के निधन के बाद अन्नाद्रमुक के हिंदुत्व की विचारधारा से दूर होने के कारण रिक्त हुए स्थान को भरने की भाजपा में काफी क्षमता है।

उन्होंने आगे कहा, जयललित जब तक जीवित थीं, तब तक वह किसी अन्य की तुलना में कहीं बेहतर हिंदुत्व नेता थीं। वर्ष 2014 से पहले जब आपके पास भाजपा जैसी पार्टी थी और नेता के रूप में जयललिता थीं, तो हिंदू मतदाता की स्वभाविक पसंद जयललिता थी। जिन्होंने अपनी हिंदुत्व पहचान को सार्वजनिक तौर पर जाहिर किया था।

अन्नामलाई ने कहा कि भाजपा के नेताओं के अलावा जयललिता देश की पहली राजनेता थीं, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे का समर्थन किया था। उन्होंने 2002-03 में तमिलनाडु में धर्मांतरण रोधी कानून बनाया था। उन्होंने आगे कहा, जयललिता ने धर्मांतरण रोधी कानून बनाया, मंदिरों को दान दिया, श्रीरंगम से चुनाव लड़ा, बड़े पैमाने पर मंदिरों के पुनरुद्धार करने के प्रयास किए और सभी प्रमुख मंदिरों को हाथी उपहार में दिए। उनकी गतिविधियों पर नजर डालें तो वह कहीं बेहतर हिंदू नेता थीं।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा, 2016 में जयललिता के निधन के बाद अन्नाद्रमुक ने हिंदुत्व के आदर्शों से किनारा किया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) से हाथ मिलाया, जिसे प्रतिबंधित इस्लामी संगठन पीएफआई की राजनीतिक शाखा माना जाता है। उन्होंने कहा, तमिलनाडु में पहली बार हिंदू एक समूह के रूप में किसी ऐसी पार्टी की तलाश कर रहे हैं, जो उनके मंदिरों की रक्षा करेगी, तो स्वभाविक रूप से वह पार्टी भाजपा है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023